

एक्जिमिअसः निर्यात लाभ

इस अंक में

- भारत के निर्यातों और प्रमुख क्षेत्रों पर यूएसए के टैरिफ का प्रभाव
- खनिज सुरक्षा मिलने पर पूरी होगी भारत की हरित यात्रा
- भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार व निवेश संबंध: आर्थिक लाभ की नई संभावनाएं
- भारत का रक्षा उपकरण उद्योग
- वैश्विक एकीकरण और संरक्षणवादी उपायों के प्रभाव

संपादकीय टीम:

श्री विश्वनाथ जंध्याला, उप महाप्रबंधक
सुश्री अल्फिया अंसारी, प्रबंधक



का तिमाही प्रकाशन

केन्द्र एक भवन, 21 वीं मंजिल,
विश्व व्यापार केन्द्र संकुल,
कफ़ परेड, मुंबई - 400 005.

फोन: 022 2217 2600

ईमेल: ccg@eximbankindia.in

www.eximbankindia.in

www.eximmitra.in



भारत के निर्यातों और प्रमुख क्षेत्रों पर यूएसए के टैरिफ का प्रभाव

– जाह्नवी सिंह, सहायक महाप्रबंधक
नेहा रामन, प्रबंधक

पृष्ठभूमि

यूएसए ने अपने व्यापारिक साझेदार देशों से आयात पर देश-वार शुल्क लगाने के उद्देश्य से अप्रैल 2025 में 'रेसिप्रोकल टैरिफ मैट्रिक्स' लागू किया था। इसमें दवाइयों, महत्वपूर्ण खनिजों और चुनिंदा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को इस टैरिफ से मुक्त रखा गया था। इसके बाद, टैरिफ बढ़ाने के निर्णय को 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान, चीन को छोड़कर अन्य सभी देशों पर 10% का समान टैरिफ लगाया गया।

जुलाई 2025 की शुरुआत में यूएसए ने टैरिफ बढ़ोतरी को 1 अगस्त, 2025 तक के लिए टाल दिया। इसके बाद 31 जुलाई, 2025 को यूएसए ने भारत से किए जाने वाले आयात पर 2 टैरिफ लगाने की घोषणा की। इसके तुरंत बाद, 6 अगस्त, 2025 को यूएसए ने 27 अगस्त, 2025 से भारतीय वस्तुओं पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ भी लगाने की घोषणा की। तदनुसार, भारत से आयात की जाने वाली चुनिंदा वस्तुओं के आयात पर यूएसए द्वारा लगाया गया टैरिफ 50% से भी अधिक हो गया।

यूएसए हमारे देश से ई-कॉमर्स निर्यातों के लिए एक अहम बाज़ार है। यूएसए ने 29 अगस्त, 2025 से 800 यूएस डॉलर की छूट वाला 'डी मिनिमिस' नियम समाप्त कर दिया है। इस नियम के अंतर्गत कम कीमत वाली वस्तुओं को यूएसए भेजना शुल्क मुक्त होता था और इसमें कागजी कार्रवाई न्यूनतम होती थी। इस बदलाव का ई-कॉमर्स निर्यातकों पर बड़ा असर पड़ेगा और इनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी।

यूएस टैरिफ के बीच हालिया ट्रेंड और धारणाएं

यूएसए द्वारा बढ़ते संरक्षणवादी उपायों के चलते, भारतीय निर्यातकों को अपनी अल्पावधि और दीर्घावधि रणनीतियों पर फिर से विचार करना होगा, ताकि वे बाज़ार में अपनी हिस्सेदारी को बचा सकें और प्रतिस्पर्धा बनाए रख सकें। शुरुआती संकेत बताते हैं कि इससे निपटने के लिए निर्यातकों ने कई उपचारात्मक पहलें की हैं। वे सामान पहले ही भेजने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि टैरिफ का असर कम हो, जोखिम कम करने के लिए आपूर्ति शृंखला के अलग-अलग मॉडल अपना रहे हैं, अधिक लाभ वाले और ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से बने उत्पादों पर फोकस कर रहे हैं। साथ ही, नए देशों और बाज़ारों में अपना कारोबार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस टैरिफ बढ़ोतरी के बीच उभरते कुछ प्रमुख ट्रेंड और धारणाएं निम्नलिखित अनुसार हैं:

- **निर्यात पहले भेजना (निर्यात की फ्रंटलोडिंग):** भारतीय निर्यातक यूएस टैरिफ के असर को थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन कम करने के लिए माल समय से पहले ही भेज रहे हैं। अप्रैल-अगस्त 2025 के दौरान, यूएसए को भारत के निर्यात में वर्ष दर वर्ष 18% की वृद्धि हुई है, इसकी तुलना में, भारत का मर्चेंडाइज़ निर्यात केवल 2.5% तक ही बढ़ा है।

- **ई-कॉमर्स निर्यातकों की आपूर्ति रणनीति में परिवर्तन:** पोस्टल नेटवर्क, ड्रॉप शिपिंग या डीडीयू मॉडल का इस्तेमाल करने वाले जो ई-कॉमर्स निर्यातक पहले 'डी मिनिमिस' नियम पर निर्भर थे, वे अब अपनी आपूर्ति रणनीति बदल रहे हैं। तदनुसार, अब वे सीधे ग्राहकों को छोटे-छोटे पार्सल भेजने के बजाय यूएसए के लोकल वेयरहाउस को एक साथ बड़े पार्सल भेज रहे हैं, ताकि बार-बार कस्टम क्लियरेंस का झंझट कम हो सके।
- **उच्च-लाभ वाले, कस्टमाइज्ड उत्पादों और बंडल प्राइसिंग पर फोकस करना:** निर्यातक अब प्रीमियम टेक्निकल टेक्सटाइल्स और विशेष रसायन (स्पेशलिटी केमिकल्स) जैसे उच्च-मूल्य वाले और कस्टमाइज्ड उत्पादों पर फोकस कर रहे हैं। साथ ही, वे बंडल प्राइसिंग डील कर रहे हैं, जैसे कपड़ों के साथ एसेसरीज़ भी दे रहे हैं, ताकि दोनों वस्तुओं पर एक टैरिफ लगे और शेल्व प्राइस प्रतिस्पर्धी बना रहे।
- **दीर्घावधि करार:** कई मध्यम और बड़े निर्यातकों ने अमेज़न, वॉलमार्ट और टार्गेट जैसे यूएस के बड़े आयातकों के साथ दीर्घावधि के ऑफ-टेक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसे करार मांग और लाभ को स्थिर रखने में मदद करते हैं, इसीलिए निर्यातक इन्हें प्राथमिकता दे रहे हैं।

गोल्डमैन साक्स के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, जून 2025 तक लागू किए गए सभी टैरिफ का केवल 14% व्यय ही निर्यातकों को स्वयं वहन करना पड़ा है। हालांकि, हाल ही में लागू हुए टैरिफ के साथ इस आंकड़े के 25% तक बढ़ जाने की संभावना है। इसके अनुसार, लगभग 22% टैरिफ लागत उपभोक्ताओं द्वारा वहन की गई है, जबकि 64% टैरिफ लागत अमेरिकी कंपनियों द्वारा वहन की गई है।

यूएसए के टैरिफ का भारत के निर्यातों और प्रमुख क्षेत्रों पर प्रभाव

इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, भारत से किए जाने वाले आयात पर टैरिफ वृद्धि के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। भारत के कुल निर्यातों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल निर्यातों में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 47% की रही, जो टैरिफ से प्रभावित नहीं होगी। तथापि, भारत के मर्चेंडाइज़ निर्यात के प्रभावित होने की संभावना है, क्योंकि 2024-25 में, भारत के कुल मर्चेंडाइज़ निर्यात का लगभग 19.8% हिस्सा यूएसए द्वारा आयात किया गया। तथापि, टैरिफ दरों और यूएसए के बाजार पर निर्भरता को देखते हुए, इसका प्रभाव अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न हो सकता है।

छूट की श्रेणी में आने वाली वस्तुएं: टैरिफ वृद्धि उन चुनिंदा वस्तुओं पर लागू नहीं होती, जो 02 अप्रैल, 2025 के एक्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर 14257 के परिशिष्ट-II में सूचीबद्ध हैं। साथ ही, 50 यू.एस.सी. 1702 (बी) के अंतर्गत उल्लिखित वस्तुएं भी छूट की श्रेणी में आती हैं, जिनमें स्मार्टफोन जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं शामिल हैं। इसमें लगभग 558 उत्पाद (एचएस 6-अंकीय स्तर पर) आते हैं। 2024 में, इस क्षेत्र से यूएसए ने भारत से 27.26 बिलियन यूएस डॉलर का आयात किया, जो भारत से निर्यातित कुल मर्चेंडाइज़ निर्यातों का लगभग 29.9% रहा। एक्ज़िम बैंक द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार, भारत से यूएसए को निर्यात किए जाने वाले 99.7% से अधिक फार्मास्यूटिकल और 81.3% से अधिक जैविक रसायन छूट की श्रेणी में आते हैं।

तालिका 1: ऐसे प्रमुख क्षेत्र, जिनके निर्यात छूट की श्रेणी में आते हैं

एचएस कोड	एचएस विवरण	भारत से यूएसए को किए जाने वाले निर्यातों में हिस्सेदारी (विव 2025)	टैरिफ से छूट प्राप्त निर्यातों की हिस्सेदारी	टैरिफ के बावजूद प्रतिस्पर्धी रहने वाले निर्यातों की हिस्सेदारी ¹	प्रतिस्पर्धा से हट जाने वाले निर्यातों की हिस्सेदारी
85	इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी	18.4	49.6 **	2.5	47.9**
30	फार्मास्यूटिकल उत्पाद	11.3	99.7	0.3	0
27	खनिज ईंधन	4.9	100	0.0	0
29	जैविक रसायन	3.1	81.3	1.7	17.1

** कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद छूट की श्रेणी में आते हैं, लेकिन मशीनरी से जुड़े उत्पाद इस श्रेणी में शामिल नहीं हैं।

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, आईटीसी ट्रेड मैप, Whitehouse.gov, एक्ज़िम बैंक रिसर्च

चुनिंदा उत्पादों में बरकरार रहेगी भारत की मूल्य प्रतिस्पर्धा: एक्ज़िम बैंक के विश्लेषण के अनुसार, भारत द्वारा यूएसए के बाजार में 713 उत्पादों (एचएस 6-अंकीय स्तर पर) में मूल्य प्रतिस्पर्धा बने रहने की उम्मीद है। यूएसए को भारत से कुल मर्चेंडाइज़ निर्यातों में इन उत्पादों की हिस्सेदारी लगभग 13.9% की होती है। इन उत्पादों के निर्यात मूल्य के विश्लेषण से पता चलता है कि 50% टैरिफ वृद्धि के बावजूद इन वस्तुओं के संबंध में, भारत यूएसए के बाजार में प्रतिस्पर्धी बना रहेगा।

तालिका 2: ऐसे प्रमुख क्षेत्र, जिनके निर्यात प्रतिस्पर्धी बने रहने की संभावना है

एचएस कोड	एचएस विवरण	भारत से यूएसए को किए जाने वाले निर्यातों में हिस्सेदारी (विव 2025)	टैरिफ से छूट प्राप्त निर्यातों की हिस्सेदारी	टैरिफ के बावजूद प्रतिस्पर्धी रहने वाले निर्यातों की हिस्सेदारी ²	प्रतिस्पर्धा से हट जाने वाले निर्यातों की हिस्सेदारी
71	रत्न और आभूषण	11.5	0.2	60.3	39.5
42	चमड़े से निर्मित उत्पाद	0.9	0	55.4	44.6

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, आईटीसी ट्रेड मैप, Whitehouse.gov, एक्ज़िम बैंक रिसर्च

नकारात्मक रूप से प्रभावित होने वाली चुनिंदा निर्यात श्रेणियां: एक्ज़िम बैंक के आकलनों के अनुसार, यूएसए द्वारा टैरिफ बढ़ाने से भारत के 4,038 से अधिक उत्पादों (एचएस 6-अंकीय स्तर पर) के निर्यातों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। यूएसए को भारत से निर्यातित मर्चेंडाइज़ उत्पादों

¹ यूएसए द्वारा आयातित उत्पादों के औसत यूनिट वैल्यू प्राइस की तुलना में भारतीय वस्तुओं के यूनिट वैल्यू प्राइस के विश्लेषण के आधार पर।

² इंडिड

में भारत की मूल्य प्रतिस्पर्धा के गंभीर रूप से प्रभावित होने की भी आशंका है। वर्ष 2024 में यूएसए को भारत के मर्चेन्डाइज़ निर्यात में इन उत्पादों का योगदान सबसे ज्यादा रहा। कुल निर्यातों में 56.2% की हिस्सेदारी इन्हीं उत्पादों की रही, जिसकी कीमत लगभग 51.3 बिलियन यूएस डॉलर रही। वर्ष 2025³ के दौरान, भारत के इन उत्पादों के निर्यात में लगभग (-)17.0% तक गिरावट हो जाने की आशंका है। कुछ क्षेत्रों में, तीव्रता से निर्यात घट सकता है। इन क्षेत्रों में अन्य के साथ-साथ मशीनरी और यांत्रिक उपकरण, टेक्सटाइल, ऑटोमोटिव, लोहे और स्टील की वस्तुएं, फर्नीचर तथा समुद्री उत्पाद शामिल हैं।

तालिका 3: ऐसे प्रमुख क्षेत्र, जिनके निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा

एचएस कोड	एचएस विवरण	भारत से यूएसए को किए जाने वाले निर्यातों में हिस्सेदारी (विव 2025)	टैरिफ से छूट प्राप्त निर्यातों की हिस्सेदारी	टैरिफ के बावजूद प्रतिस्पर्धी रहने वाले निर्यातों की हिस्सेदारी	प्रतिस्पर्धा से हट जाने वाले निर्यातों की हिस्सेदारी
84	मशीनरी एवं यांत्रिक उपकरण	7.7	0	15.9	84.1
73	लोह / स्टील निर्मित वस्तुएं	3.6	0	24.5	75.5
63	अन्य कृत्रिम टेक्सटाइल से निर्मित वस्तुएं	3.4	0	0.4	99.6
62	अपैरल और परिधान ऐसेसरीज़ वाली वस्तुएं (जो बुने या क्रोशिया से न बने हों)	3.1	0	3.7	96.3
61	अपैरल और परिधान ऐसेसरीज़ वाली वस्तुएं (बुनी हुई या क्रोशिया से बुनी हुई)	3.1	0	0.3	99.7
87	परिवहन	3.0	0	20.3	79.7
3	मछली और कवचधारी झींगा	2.4	0	0.7	99.3
39	प्लास्टिक और वस्तुएं	1.9	11.6	6.0	82.4
57	कार्पेट और टेक्सटाइल से निर्मित अन्य फ्लोर कवरिंग	1.4	0	0.0	100
38	विविध रासायनिक उत्पाद	1.4	15.6	5.9	78.5
94	फर्नीचर	1.3	0	2.0	98
68	पत्थर, प्लास्टर, सीमेंट, एस्बेस्टस, अभ्रक या इसी तरह की सामग्री से बनी वस्तुएं	1.1	0	7.6	92.4
90	दृष्टि संबंधी, फोटोग्राफिक और चलचित्र उपकरण	1.1	0	19.7	80.3
40	रबड़ और इसकी वस्तुएं	1.1	0.5	21.6	77.9
76	एल्युमिनियम और इसकी वस्तुएं	1.0	0	14.4	85.6

एचएस कोड	एचएस विवरण	भारत से यूएसए को किए जाने वाले निर्यातों में हिस्सेदारी (विव 2025)	टैरिफ से छूट प्राप्त निर्यातों की हिस्सेदारी	टैरिफ के बावजूद प्रतिस्पर्धी रहने वाले निर्यातों की हिस्सेदारी	प्रतिस्पर्धा से हट जाने वाले निर्यातों की हिस्सेदारी
16	मांस, मछली और कवचधारी झींगा से बनी प्रसंस्कृत वस्तुएं	0.7	0	0.0	100
72	लोहा और स्टील	0.7	20.7	1.2	78.1
33	सुगंधित तेल	0.6	0	42.2	57.8
48	कागज और इसकी वस्तुएं	0.5	0.2	23.2	76.6

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, आईटीसी ट्रेड मैप, Whitehouse.gov, एक्जिम बैंक रिसर्च

निर्यातों पर समग्र प्रभाव: वर्ष 2025 में, यूएसए को भारत के कुल निर्यात में लगभग 6.1% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि बने रहने की उम्मीद है। इसका मुख्य कारण है कि भारत के लगभग 43.8% निर्यात पर यूएसए द्वारा बढ़ाए गए टैरिफ का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें वे उत्पाद शामिल हैं, जिन पर छूट मिली है और वे भी जिनमें भारत कीमत के मामले में प्रतिस्पर्धी रहेगा। इसके अलावा, भारतीय निर्यातकों ने पहले से ही बड़ी मात्रा में माल भेज दिया है।

निर्यात उन्मुखता, यूएस बाजारों पर निर्भरता और निर्यातों पर प्रभाव के आधार पर समग्र प्रभाव: यूएस टैरिफ में हुई बढ़ोतरी के चलते विविध क्षेत्र कुल मिलाकर कितने प्रभावित होंगे। यह समझने के लिए, यूएस बाजार पर भारतीय निर्यातकों की निर्भरता और हर उत्पाद श्रेणी की निर्यात उन्मुखता का विश्लेषण किया गया है। यूएसए द्वारा बढ़ाए गए टैरिफ के चलते इससे सबसे ज्यादा समुद्री उत्पाद प्रभावित होंगे। क्योंकि, एक तो यह क्षेत्र निर्यात पर बहुत ज्यादा निर्भर है और दूसरा, यह यूएस के बाजार पर निर्भर है। दूसरी ओर, फार्मास्यूटिकल्स, जैविक रसायन, पेट्रोलियम उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक्स पर इस टैरिफ का प्रभाव बहुत कम होगा, क्योंकि इन पर टैरिफ वृद्धि लागू नहीं की गई है। इसके अलावा भी कुछ उत्पाद हैं, जिन पर टैरिफ वृद्धि से प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि न तो ये निर्यात उन्मुख हैं और न ही यूएस बाजार पर उतने निर्भर हैं। ऐसे क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल और अलौह धातु शामिल हैं। अन्य क्षेत्रों पर टैरिफ वृद्धि का प्रभाव मध्यम रहने की संभावना है।

समग्र निम्न प्रभाव

- अलौह धातु
- ऑटोमोबाइल और ऑटो पुर्जे

समग्र मध्यम से उच्चतम प्रभाव

- समुद्री उत्पाद
- प्लास्टिक उत्पाद
- रत्न और आभूषण
- इलेक्ट्रिकल और नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी
- चमड़े से निर्मित उत्पाद
- लौह धातु और इससे निर्मित उत्पाद
- अपैरल और परिधान
- पेपर और संबंधित वस्तुएं
- रबड़ के उत्पाद
- सीमेंट और ग्रेनाइट
- विविध रासायनिक उत्पाद,
- लकड़ी और लकड़ी से निर्मित उत्पाद
- विविध विनिर्मित वस्तुएं

खनिज सुरक्षा मिलने पर पूरी होगी भारत की हरित यात्रा

– राहुल मजूमदार, उप महाप्रबंधक
धितिका शाह, अधिकारी

ऐसे अधात्विक खनिजों को महत्वपूर्ण खनिज कहा जाता है, जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हैं और जिनमें आपूर्ति बाधित होने का जोखिम बना रहता है। इनमें तांबा, लिथियम, निकेल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और दुर्लभ मृदा तत्व (आरईई) शामिल हैं। ये खनिज देश के दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, अंतरिक्ष और रक्षा उपकरणों जैसे प्रमुख उद्योगों के लिए अनिवार्य तत्व होते हैं। ये खनिज किसी देश की अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी प्रगति के लिए बेहद जरूरी होते हैं। साथ ही, ये खनिज हमें न्यून कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में भी मदद करते हैं, क्योंकि इनका उपयोग पवन टरबाइन, सौर पैनल और इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों जैसी स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों में किया जाता है।

इस समय दुनियाभर में महत्वपूर्ण खनिजों की मांग लगातार तेजी से बढ़ रही है। इसका बड़ा कारण है कि कई देशों ने 'नेट जीरो' लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबद्धता ली है और वे इस लक्ष्य अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस वजह से महत्वपूर्ण खनिज और भी दुर्लभ हो गए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि खनिजों की खदान और इनके शोधन का कार्य कुछ ही देशों में, विशेष रूप से चीन में केंद्रित है। ऐसे में भारत जैसे देश, जो 2030 तक अपनी ऊर्जा का 50% कार्बन मुक्त और 500 गीगावॉट जीवाश्म ईंधन-मुक्त क्षमता हासिल करना चाहते हैं, इन्हें अपनी महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए समय रहते तेजी से उपाय करने होंगे।

वैश्विक परिदृश्य

वर्ष 2023 में महत्वपूर्ण खनिजों की मांग में अच्छी वृद्धि रही। इस दौरान, लिथियम की मांग 30% और निकेल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और दुर्लभ मृदा तत्व (आरईई) की मांग 8% से 15% तक बढ़ गई। इसी वर्ष, स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों का उत्पादन, महत्वपूर्ण खनिजों की मांग बढ़ने का सबसे बड़ा कारण रहा। इस उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण खनिजों की कुल वैश्विक मांग 10,111.5 किलो टन रही। इसमें तांबे की मांग सबसे ज्यादा, 6371.7 रही, जिसका सबसे ज्यादा उपयोग बिजली नेटवर्क और सोलर पीवी में हुआ। लिथियम की लगभग 60% वैश्विक मांग केवल स्वच्छ ऊर्जा तकनीक क्षेत्र से रही, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उद्योग अग्रणी रहा।

आपूर्ति के मामले में, खनिजों की खुदाई और परिष्करण (माइनिंग और रिफाइनिंग) दोनों ही काम कुछ गिने-चुने देशों में केंद्रित हैं। इनमें चीन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, खासकर आपूर्ति श्रृंखला के मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम हिस्सों में। चीन, महत्वपूर्ण खनिजों का सबसे बड़ा आयातक होने के साथ-साथ दुनिया का सबसे बड़ा खनिज शोधन केंद्र भी है। प्राकृतिक ग्रेफाइट और डिस्प्रोसियम की रिफाइन आपूर्ति का 100%, कोबाल्ट का 70%, और लिथियम व मैंगनीज़ का लगभग 60% हिस्सा चीन से आयात किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि इस उद्योग में चीन की स्थिति बेहद मजबूत है।

भारतीय परिदृश्य

वर्ष 2023 में, खान मंत्रालय ने एक अंतर-मंत्रालयी समिति के जरिए भारत के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिज चिह्नित किए थे। यह चयन दो मुख्य आधारों पर किया गया – 'आर्थिक महत्व (ईआई)' और 'आपूर्ति जोखिम (एसआर)'। तदनुसार, कोबाल्ट, लिथियम, निकेल और ग्रेफाइट जैसे खनिजों को उच्च आर्थिक महत्व और उच्च आपूर्ति जोखिम दोनों श्रेणियों में रखा गया है। इन 30 में से 10 खनिजों के लिए भारत पूरी तरह आयात पर निर्भर है।

इसे ध्यान में रखते हुए, सतत खनिज आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा दो महत्वपूर्ण नीतियां अपनाई जा रही हैं। एक, देश में खनिजों की खोज और खनन बढ़ाना, और दूसरी, विदेशों में खनिज संपत्तियां हासिल करना। केंद्रीय बजट 2025-26 में खनन क्षेत्र को अगले पांच वर्षों में सुधारात्मक परिवर्तनों के लिए चुने गए छह क्षेत्रों में शामिल किया गया है। 12 महत्वपूर्ण खनिजों के स्क्रेप और अपशिष्ट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) हटाने की भी घोषणा की गई है। जनवरी 2025 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम)' को ₹16,300 करोड़ के खर्च और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों व अन्य संस्थाओं से ₹18,000 करोड़ के निवेश के साथ मंजूरी दी है। 2023 में खनन और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में भी संशोधन किया गया, ताकि महत्वपूर्ण और गहराई में छिपे खनिजों की खोज और खनन बढ़ाया जा सके। इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने, महत्वपूर्ण खनिजों के लिए नीलामी और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए 'एक्सप्लोरेशन लाइसेंस' जैसी व्यवस्थाएं शामिल की गई हैं। मार्च 2024 तक, केंद्र सरकार द्वारा चार चरणों में 48 खनिज ब्लॉकों में से 24 ब्लॉकों की सफल नीलामी कर दी गई है। इनमें सबसे ज्यादा ब्लॉकों की नीलामी अरुणाचल प्रदेश में हुई है। इसके अलावा, सरकार द्वारा विदेशों में खनिज संपत्ति हासिल करने के लिए 'खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल – केएबीआईएल)' की स्थापना भी की गई है।

वित्तीय वर्ष 2024 में भारत ने कई देशों से महत्वपूर्ण खनिजों का आयात किया। विविध खनिजों के लिए विविध देशों से किए गए आयात में अन्य के साथ-साथ बेलजियम और आयरलैंड से लिथियम, ऑस्ट्रेलिया और जापान से निकेल, चीन और बेलजियम से कोबाल्ट तथा मेडागास्कर और चीन से ग्रेफाइट का आयात करना शामिल है। उल्लेखनीय है कि भारत 2018 के बाद से ही तांबे का निवल आयातक बना हुआ है।

अनुशांसाएं और संभावनाएं

खनिजों की रिकवरी और रीसाइक्लिंग बाजार का विकास

भारत अब खनिजों की रिकवरी और रीसाइक्लिंग बाजार को विकसित करने पर ध्यान दे सकता है। इसके दो उद्देश्य हैं – पहला, खनिजों की आपूर्ति के लिए एक द्वितीय स्रोत तैयार करना और दूसरा, लगातार खनन से होने वाले

पर्यावरणीय और सामाजिक दुष्प्रभावों को कम करना। बढ़ते ई-अपशिष्ट को देखते हुए 'शहरी खनन' पर केंद्रित एक अलग नीति बनाई जा सकती है, जिससे मोबाइल फोन, प्लास्टिक और निर्माण सामग्री के अपशिष्ट से महत्वपूर्ण खनिज निकाले जा सकें। इसके साथ ही, खनिज रीसाइक्लिंग को तेजी से बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की जा सकती है। रीसाइक्लिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने और रीसाइक्लिंग कंपनियों को सीधे सब्सिडी देने जैसी पहलें भी शुरू की जा सकती हैं।

खनिज प्रसंस्करण तकनीक का विकास

भारत को खनिज प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि दुनिया में इन खनिजों का प्रसंस्करण कुछ ही जगहों पर केंद्रित है। इसलिए देश में बड़े पैमाने पर प्रसंस्करण सुविधाएं और मूल्य संवर्धन तकनीकें विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण है। खनिज प्रसंस्करण तकनीकें महंगी और पूंजीगत लागत वाली होती हैं, इसलिए इन सुविधाओं में बड़े निवेश की आवश्यकता होगी। उन्नत तकनीक हासिल करने के लिए हमें अग्रणी वैश्विक कंपनियों से तकनीक स्थानांतरण पर या फिर भारत की विदेशी खनिज संपत्तियों के पास संयुक्त रूप से प्रसंस्करण संयंत्र विकसित करने पर ध्यान देना होगा। खनिज-समृद्ध राज्यों में 'क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग पार्क' स्थापित करने से भी भारत की प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाने, आपूर्ति शृंखला को सुदृढ़ करने और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।

अंतरराष्ट्रीय साझेदारियां बढ़ाना

खनिज-समृद्ध देशों के साथ आपूर्ति शृंखला के हर चरण में साझेदारी करना भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए महत्वपूर्ण खनिजों की राष्ट्रीय भंडारण प्रणाली शुरू की जा सकती है, ताकि द्विपक्षीय करारों या क्षेत्रीय समूहों के साथ इसकी आपूर्ति सुरक्षित की जा सके। साझेदारी के अन्य संभावित क्षेत्रों में ऑफटेक करार और खनिज खोज व खनन से जुड़े करार शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, आपूर्ति शृंखला में लॉजिस्टिक से संबंधित चुनौतियों को कम करने के लिए लोबिटो कॉरिडोर रेल लिंक जैसी अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं का लाभ उठाकर सुदृढ़ साझेदारी की जा सकती है।

विदेशों से महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन

विदेशों से महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विवेकसम्मत फैसले लेने और आवश्यक नीतिगत पहलों को दिशा देने वाली एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन करना आवश्यक है। विशेषकर, भारत के विदेशी खनिज से संबंधित ट्रांज़ैक्शनों के मामले में निर्णय लेने के लिए इस समिति का होना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान में, सार्वजनिक क्षेत्र की कई कंपनियां और संबंधित कार्यालय खान मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं, जबकि आईआरईएल (इंडिया लिमिटेड) जैसी इस क्षेत्र की अन्य संस्थाएं परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती हैं। ऐसे में, उक्त समिति यह सुनिश्चित करेगी कि महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े रणनीतिक विषयों पर होने वाला विचार-विमर्श सभी संबंधित मंत्रालयों की सहमति से हो।

महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में उभरती तकनीकों को अपनाना

भारत को महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में उभरती तकनीकों को अपनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) जैसी तकनीकों के इस्तेमाल से इस क्षेत्र की पूरी आपूर्ति शृंखला में दक्षता और उत्पादकता बढ़ेगी। इन तकनीकों के बहुत से लाभ हैं; इनसे भूगर्भीय डेटा का रियल-टाइम विश्लेषण हो सकेगा, पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नंस (ईएसजी) मानकों का बेहतर पालन होगा, खनन के काम आने वाले उपकरणों की प्रीडिक्टिव मेंटेनेंस संभव होगी, खनिज आपूर्ति की पारदर्शी ट्रेसिंग होगी और ऑटोमेशन से कर्मचारियों की सुरक्षा भी बढ़ेगी आदि। प्रस्तावित 'क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग पार्क' में इन तकनीकों के उपयोग से आपूर्ति शृंखला को बेहतर बनाने और इसे केंद्रीकृत करने में मदद मिलेगी।

भारत के खनन क्षेत्र के लिए ईएसजी फ्रेमवर्क में सुधार

संपोषी औद्योगिक प्रथाएं अपनाने पर बढ़ते जोर के साथ, भारत को अपने खनन क्षेत्र में ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नंस) प्रथाओं को बेहतर बनाने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। वैश्विक निवेशक अब हरित ऊर्जा समाधानों को अपनाने और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप काम करने पर जोर दे रहे हैं। ऐसे में, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भारत, खनन कंपनियों को ईएसजी सिद्धांतों का पालन करने के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी कर सकता है। इसके अलावा, खनन क्षेत्र के लिए विशेष ईएसजी सिद्धांत तैयार करने पर फोकस करने के लिए अलग से एक कार्य समूह का गठन करना भी उपयोगी हो सकता है।

निधि तंत्र पर फोकस

भारत खनन परियोजनाओं के लिए फंडिंग के नए तरीकों पर ध्यान दे सकता है। इसमें सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मॉडल अपनाना और वित्तीय जोखिम कम करने के लिए एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) बनाना शामिल है। एक अन्य विकल्प के रूप में, उत्पादन और खनिज रीसाइक्लिंग के लिए उन्नत तकनीकें प्रदान करने वाली निजी कंपनियों के साथ ऑफटेक करार करना शामिल है। इसके अलावा, खनिज प्रसंस्करण के लिए एक नवेन्मेषी निधि तैयार की जा सकती है, क्योंकि यह आपूर्ति शृंखला का सबसे अधिक शोध एवं विकास वाला चरण है। खनिज रिकवरी और रीसाइक्लिंग मार्केट को बढ़ावा देने के लिए हरित बॉन्ड का उपयोग किया जा सकता है। भारत खनिज-समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं के साथ काउंटरट्रेड मैकेनिज़्म के विकल्प पर भी विचार कर सकता है, जिसके लिए एक व्यापक नीति बनाई जा सकती है।

अतः यह कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण खनिज आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत अहम हैं। इन खनिजों तक सीमित पहुंच के चलते अर्थव्यवस्थाएं अस्थिर आपूर्ति शृंखला के जोखिम में आ जाती हैं। यही कारण है कि भारत को सुदृढ़ खनिज आपूर्ति बेस बनाने के प्रयास तेज करने होंगे, ताकि ऐसे उद्योगों का विकास सुनिश्चित किया जा सके जो हमारी आर्थिक संप्रभुता के लिए आवश्यक हैं और साथ ही न्यून कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था की ओर भी सुगमता के साथ बदलाव लाया जा सके। ■

भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार व निवेश संबंध: आर्थिक लाभ की नई संभावनाएं

- सृजिता नंदी, प्रबंधक
विशाखा भागवत, अधिकारी

कजाकिस्तान, किर्गिजस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान को संयुक्त रूप से मध्य एशिया के नाम से जाना जाता है। तेजी से विकसित हो रहे इस क्षेत्र का जीडीपी, 2023 में 458 बिलियन यूएस डॉलर का था और कुल जनसंख्या 7.9 मिलियन थी। सोवियत संघ के साथ साझा इतिहास के बावजूद, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से यह क्षेत्र काफी अलग है। इस क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि दर वैश्विक और उभरते बाजारों की तुलना में अधिक रही है। इन देशों में कजाकिस्तान आर्थिक उत्पादन और जीवन स्तर में सबसे अग्रणी है, जबकि उज़्बेकिस्तान सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। इस क्षेत्र के कुल जीडीपी में कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का सबसे बड़ा योगदान है और ये तीनों मुख्यतः हाइड्रोकार्बन (तेल और गैस) का निर्यात करते हैं। वहीं, किर्गिजस्तान और ताजिकिस्तान से मुख्य तौर पर धातुओं और अयस्कों का निर्यात किया जाता है। व्यापार के मामले में, इन पांचों देशों की अर्थव्यवस्थाएं खुली हैं, जिनमें किर्गिजस्तान सबसे अधिक व्यापार-निर्भर देश है।

भारत की जनसंख्या 1.4 बिलियन है और 2023 में यह दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। 2023 में भारत का नॉमिनल जीडीपी 3.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर का रहा और यह दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। सुदृढ़ घरेलू मांग और निवेश के चलते भारत ने 2023 में 8.2% की वृद्धि दर हासिल कर ली है। इससे देश 2023 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया। वैश्विक व्यापार में भी भारत की भूमिका अहम रही। भारत मर्चेंडाइज़ निर्यातों में 17वें पायदान पर और आयात में 8वें पायदान पर रहा। वैश्विक मर्चेंडाइज़ व्यापार के कुल मूल्य में भारत का योगदान 2.3% का रहा।

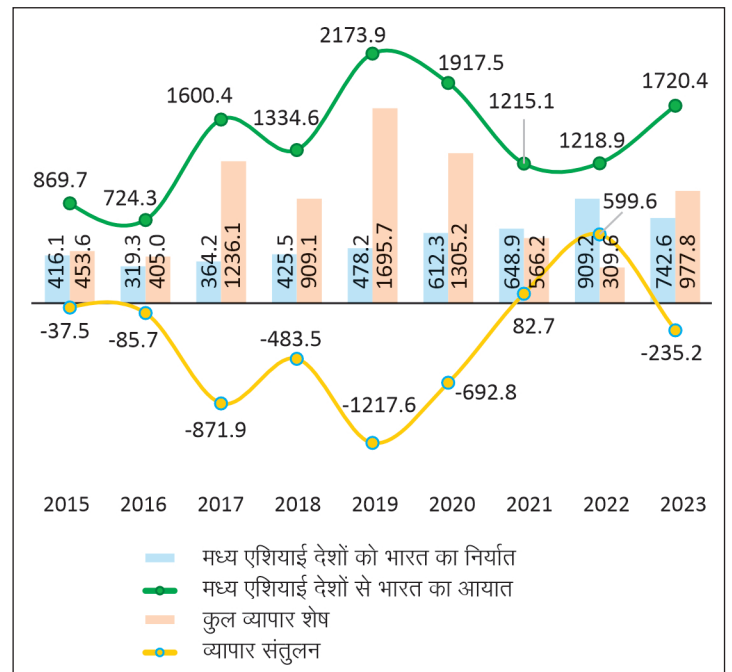
भारत के साथ मध्य एशियाई देशों के द्विपक्षीय व्यापार संबंध

एशिया और यूरोप को मिलाने वाला रास्ता मध्य एशिया से गुजरता है। ऐसे में, मध्य एशिया अपनी रणनीतिक लोकेशन के कारण, भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक क्षेत्र है। ऊर्जा संसाधनों, खनिजों और उपजाऊ लेकिन अभी तक न्यूनतम उपयोग की गई कृषि भूमि से भरपूर यह क्षेत्र, भारत को कई बड़े अवसर प्रदान करता है। भारत अपनी ऊर्जा और औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ कृषि सहयोग को भी सुदृढ़ कर सकता है। इसके लिए भारत अपनी उन्नत कृषि व्यवसाय तकनीकों और विशेषज्ञता के माध्यम से मध्य एशिया के कृषि क्षेत्र को आधुनिक रूप देने में मदद कर सकता है। यह साझेदारी सुरक्षा, ऊर्जा और अन्य आर्थिक व व्यवसाय अवसरों जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारे साझा हितों के अनुरूप है। भारत और मध्य एशिया इन संबंधों को सुदृढ़ करके भविष्य में परस्पर बड़े लाभ हासिल कर सकते हैं।

भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच व्यापार संबंधों में लगातार वृद्धि हुई। यह व्यापार 2010 में 490.1 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2023 में 1,720.4 मिलियन यूएस डॉलर का हो गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान, भारत से निर्यात काफी स्थिर रहा और 2010 के 272.3 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2023 में 742.6 मिलियन यूएस डॉलर का हो गया। इस दौरान, इसमें 10.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। इस दौरान मध्य एशिया से भारत का आयात बढ़ गया। इस आयात में 39.6% की एएजीआर दर्ज की गई और यह 2010 के 271.8 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2023 में 977.8 मिलियन यूएस डॉलर का हो गया। इसके विपरीत, इस अवधि में मध्य एशिया से भारत के आयात में काफी उतार-चढ़ाव की स्थिति रही। 2010 में जहां भारत ने 271.8 मिलियन यूएस डॉलर का आयात किया, वहीं 2023 में 39.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ यह आयात 977.8 मिलियन यूएस डॉलर का हो गया। 2010 में इस क्षेत्र के साथ भारत के व्यापार शेष में 54.5 मिलियन यूएस डॉलर का अधिशेष था, लेकिन 2014 से 2020 तक यह अधिशेष

घाटे में बदल गया और 2019 में यह घाटा 1.2 बिलियन यूएस डॉलर तक जा पहुंचा। महामारी के बाद निर्यात बढ़ा और इसके चलते 2021 और 2022 में पुनः अधिशेष दर्ज हुआ।

चार्ट 1. मध्य एशियाई देशों के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार (मिलियन यूएस डॉलर में)



स्रोत: आईटीसी ट्रेड मैप और इंडिया एक्जिजिटिव बैंक रिसर्च

2023 में मध्य एशियाई क्षेत्र को भारत से कुल निर्यातों में 37.9% की हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा हिस्सा फार्मास्यूटिकल्स का रहा। इसके बाद अन्य वस्तुओं के साथ-साथ विद्युत मशीनरी और उपकरण (कुल निर्यातों में 12.1% की हिस्सेदारी के साथ), मशीनरी और मैकेनिकल उपकरण (10.4%), खाने योग्य मांस (5%), तथा फल और मेवे (3.2%) शामिल रहे। वहीं, भारत ने सबसे ज्यादा आयात खनिज ईंधन और तेलों का किया। इस क्षेत्र से भारत ने कुल आयातों में 35.3% की हिस्सेदारी के साथ खनिज ईंधन और तेलों का आयात किया। इसके बाद, 2023 में किए गए अन्य आयातों में उर्वरक (कुल आयातों में 21.3% की हिस्सेदारी के साथ), अकार्बनिक रसायन (13%), लवण, चूना और सीमेंट (7.2%), तथा अयस्क, स्लैग और राख (7.1%) शामिल रहे।

पिछले एक दशक में भारत और मध्य एशिया के व्यापारिक संबंधों में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। भारत से कुल निर्यातों के 45.3% के आयात के साथ उज़्बेकिस्तान भारत का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। इससे पहले 2017 तक कजाकिस्तान शीर्ष पर था, जो अब 35% की हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर आ गया है। ताजिकिस्तान, किर्गिजस्तान और तुर्कमेनिस्तान की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम रही। वहीं, आयात के मामले में 2023 में 64.5% की हिस्सेदारी के साथ भारत कजाकिस्तान से निर्यातित माल का सबसे बड़ा आयातक रहा। इसके बाद तुर्कमेनिस्तान 21.7% के साथ दूसरे स्थान पर रहा और उज़्बेकिस्तान का योगदान 10.6% का रहा। ताजिकिस्तान और किर्गिजस्तान की हिस्सेदारी क्रमशः 2% और 1.2% की रही।

भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश साझेदारी

फायनेंशियल टाइम्स के एफडीआई मार्केट्स के अनुसार, जनवरी 2010 से दिसंबर 2023 के बीच, भारत, मध्य एशिया में कुल 10 परियोजनाओं के लिए लगभग 1.5 बिलियन यूएस डॉलर के अनुमानित निवेश के साथ 16वां सबसे बड़ा निवेशक रहा। इस अवधि में भारत ने लगभग 78.4% की हिस्सेदारी के साथ सबसे ज्यादा निवेश कज़ाकिस्तान में किया। इसके बाद, भारत ने कुल निवेश का 17.8% निवेश ताजिकिस्तान में और 3.7% निवेश उज़्बेकिस्तान में किया।

भारतीय निवेशकों के लिए मध्य एशिया का संसाधन क्षेत्र विशेष रूप से आकर्षक रहा। कुल निवेश के 1,014.7 मिलियन यूएस डॉलर के साथ सबसे अधिक निवेश कोयला, तेल और गैस जैसे पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रों में किया गया। इसके बाद, लगभग 276.6 मिलियन यूएस डॉलर के साथ अक्षय ऊर्जा क्षेत्र दूसरे स्थान पर रहा। मुख्य क्षेत्रों के अलावा, कई क्षेत्र ऐसे भी रहे, जहां भारतीय निवेश कुछ कम रहा। इनमें टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, वित्तीय सेवाएं और होटल और पर्यटन जैसे क्षेत्र शामिल रहे।

मध्य एशिया से भारत में आने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमित रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अप्रैल 2000 से मार्च 2024 के एफडीआई आंकड़ों के अनुसार कज़ाकिस्तान ने भारत में लगभग 27.3 मिलियन यूएस डॉलर का निवेश किया। इसके बाद, ताजिकिस्तान (1.4 मिलियन यूएस डॉलर), किर्गिज़स्तान (0.003 मिलियन यूएस डॉलर) और तुर्कमेनिस्तान (0.002 मिलियन यूएस डॉलर) शामिल रहे। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, उज़्बेकिस्तान ने अब तक भारत में कोई निवेश नहीं किया है।

मुख्य नीतिगत अनुशांसाएं

भारत और मध्य एशिया के बीच सुदृढ़ आर्थिक सहयोग के लिए एक स्वाभाविक तालमेल प्रदान करने वाले कई प्रमुख क्षेत्र एक-दूसरे के लिए पूरक के रूप में काम करते हैं। बेहतर कनेक्टिविटी और परिवहन मार्गों के अभाव के चलते अब तक इस क्षेत्र के अन्य साझेदार देशों की तुलना में भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध सीमित रहा है। तथापि, यह संबंध कृषि व्यवसाय, अक्षय ऊर्जा, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल, सूचना प्रौद्योगिकी व डिजिटल सेवाओं के साथ-साथ तेल और गैस जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में मिलकर काम करने से मजबूत हो सकता है।

नई संभावनाओं के आधार पर व्यापार को नई गति देना

संरचनात्मक विश्लेषण के आधार पर भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार संबंध बढ़ाने की अपार संभावनाएं सामने आई हैं। दो अंकीय एचएस कोड स्तर पर किए गए विस्तृत विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि दोनों क्षेत्रों की आयात-निर्यात मांग परस्पर अनुकूल हैं। मध्य एशिया को विद्युत उपकरण, मशीनरी, परिवहन वाहन और औषधियों जैसे उत्पादों की आवश्यकता है, ये वही क्षेत्र हैं जिनमें भारत की निर्यात क्षमता सुदृढ़ है। दूसरी ओर, भारत की ऊर्जा और औद्योगिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मध्य एशिया के पास खनिज ईंधन और तेल, कीमती धातुएं व रत्न, लौह-इस्पात और अकार्बनिक रसायन जैसे प्रमुख संसाधन उपलब्ध हैं। इन परस्पर पूरक व्यापार प्रोफाइलों से दोनों क्षेत्रों को सुदृढ़ आर्थिक सहयोग और एक दूसरे के साथ व्यापार प्रवाह का सुनहरा मौका मिलता है।

संयुक्त उद्यमों और तकनीकी सहयोग द्वारा नए बाजार में प्रवेश को सुगम बनाना

मध्य एशिया में भारतीय कंपनियों की बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए संयुक्त उपक्रमों और तकनीकी सहयोग के जरिए भारतीय उत्पादों और सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। इनमें पेट्रोकेमिकल, अक्षय ऊर्जा, टेक्सटाइल, पर्यटन, कृषि, स्वास्थ्य सेवाएं, फार्मास्यूटिकल, रसायन, इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स और परिवहन जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। इस क्षेत्र में भारत की अच्छी पहचान बनाने के लिए ज्ञान-विनिमय और निवेश बेहद जरूरी हैं। भारत और मध्य एशियाई देशों को मिलकर साझा हित वाली

परियोजनाओं के लिए सहायक एक ऐसा व्यापक औद्योगिक सहयोग ढांचा विकसित करना चाहिए, जो दे और दीर्घावधि आर्थिक साझेदारियों का आधार बन सके।

व्यापार वित्त तक पहुंच बढ़ाना

एडीबी के अनुसार, मध्य एशिया के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लगभग 57% व्यापार वित्त आवेदन खारिज हो जाते हैं, जबकि एशिया के बाकी हिस्सों में यह आंकड़ा करीब 33% है। सीमित कॉरिस्पॉन्डेंट बैंकिंग नेटवर्क और 2019 के बाद वैश्विक बैंक निकासियों के चलते सीमा-पार भुगतान और भी कठिन हो गए हैं। यह स्थिति स्थानीय बैंकों की क्षमता और संसाधनों की कमी को दर्शाती है। इस अंतर को कम करने और वित्त की उपलब्धता बढ़ाने में विकास वित्त संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। वे ऋण क्षमता बढ़ाने वाले जोखिम-साझेदारी और ट्रांज़ेक्शन गारंटी जैसे वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स उपलब्ध करा गैर-पारंपरिक पुष्टिकर्ता (कंफर्मिंग) बैंकों को सहयोग दे सकती हैं। इससे मध्य एशियाई देशों में व्यापार वित्त तक पहुंच बेहतर होगी और क्षेत्रीय व्यापार को नई गति मिलेगी।

मध्य एशियाई देशों में व्यापार और सीमा-पार आवागमन को सुगम बनाना

मध्य एशिया चूंकि एशिया और यूरोप के बीच प्रमुख व्यापार मार्गों के संगम पर पड़ता है, इसलिए मध्य एशियाई देशों में व्यापार और सीमा-पार आवागमन को सुगम बनाना इस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि यहां व्यापार से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने और यातायात व परिवहन ढांचे को सुदृढ़ करने पर इस क्षेत्र में तीव्रता से आर्थिक विकास हो सकता है। इससे इनका परस्पर व्यापार बढ़ेगा और यह क्षेत्र अपनी भौगोलिक स्थिति का सदुपयोग करते हुए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से बेहतर रूप से जुड़ पाएगा। इस तरह, मध्य एशिया एक सक्रिय, आधुनिक और समृद्ध परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में उभर सकता है।

परिवहन और लॉजिस्टिक्स में सुधार

भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार में परिवहन और लॉजिस्टिक्स संबंधी चुनौतियां हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी सक्रिय भूमि मार्ग उपलब्ध नहीं है। हवाई कनेक्टिविटी भी सीमित है, इसलिए ये केवल महंगे या जल्दी खराब हो जाने वाले सामान के लिए ही उपयुक्त है। 2022 तक अधिकतर माल सुएज़ और काला सागर बंदरगाहों के जरिए ले जाया जाता था। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर मध्य एशिया जैसे चारों तरफ से भूमि से घिरे क्षेत्र तक बेहतर पहुंच बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है, खासकर इसकी पूर्वी शाखा जो ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कज़ाकिस्तान से होकर गुजरती है। इस कॉरिडोर के विकसित होने से वैश्विक निवेश आकर्षित होने, इस क्षेत्र की समृद्धि बढ़ने और संपोषी विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आईएनएसटीसी क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देकर और भारत और मध्य एशिया, दोनों को एक-दूसरे के उभरते बाजारों में पहुंच सुलभ कराकर, इन दोनों साझेदार देशों को प्रमुख लॉजिस्टिक्स केंद्र बना देने की क्षमता रखता है।

मध्य एशिया में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए मजबूत और आधुनिक बुनियादी ढांचे की बहुत जरूरत है। इसमें रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण, सड़कों का आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स केंद्र बनाना और बॉर्डर चेकपॉइंट्स को बेहतर व सुविधाजनक बनाने जैसे उपाय शामिल हैं। इन क्षेत्रों में निवेश आकर्षित कर पूरे क्षेत्र की आर्थिक गतिशीलता बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ही, देशों के बीच नियमों का समन्वय, प्रक्रियाओं का सरलीकरण और व्यापार से जुड़ी प्रणालियों का डिजिटल रूपांतरण आदि सॉफ्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हार्ड और सॉफ्ट दोनों इन्फ्रास्ट्रक्चर मिलकर काम करते हैं, तब क्षेत्र में व्यापार सुगम होता है, अवसर बढ़ते हैं और आर्थिक सहयोग के नए रास्ते खुलते हैं। ■

भारत का रक्षा उपकरण उद्योग

– राहुल मजूमदार, उप महाप्रबंधक
साक्षी गर्ग, प्रबंधक

दुनिया निरंतर बहुध्रुवीय होती जा रही है। भू-राजनीतिक परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं और अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं। ऐसे परिवेश में सुदृढ़ रक्षा क्षमताओं का विकास करना पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है। नई तकनीकों से पारंपरिक सैन्य मानक बदल रहे हैं, जिसके चलते सरकारें अपनी सैन्य क्षमताओं के उन्नयन के लिए ज्यादा से ज्यादा संसाधन आवंटित कर रही हैं। वर्ष 2024 में विश्व का सैन्य व्यय एक नया रिकॉर्ड छू गया। इस दौरान, कुल व्यय 2.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर का रहा। यह पिछले वर्ष की तुलना में 9.4% अधिक रहा। इस दौरान, पूरी दुनिया में सैन्य व्यय बढ़ गया, खासकर यूरोप और मध्य पूर्व में यह व्यय तेजी से बढ़ा। इस क्षेत्र में, पांच सबसे ज्यादा व्यय करने वाले देशों में यूएस, चीन, रूस, जर्मनी और भारत शामिल रहे। इन पांचों देशों ने कुल वैश्विक व्यय का 60% यानी लगभग 1.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर खर्च किया¹। भारत ने भी 2024 में अपने जीडीपी का 2.3% व्यय रक्षा क्षेत्र पर किया था। यह प्रतिशत चीन और जर्मनी से ज्यादा है, लेकिन सऊदी अरब, रूस और यूएस के मुकाबले कम है।

सैन्य क्षेत्र पर सबसे ज्यादा व्यय करने वाले देश

देश	2023 में किया गया व्यय (बिलियन यूएस डॉलर)	2024 में किया गया व्यय (बिलियन यूएस डॉलर)	वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन	2024 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यय
यूएस	916.0	997.3	8.9%	3.4%
चीन	296.8	313.7	5.7%	1.7%
रूस	109.2	149.0	36.4%	7.1%
जर्मनी	67.3	88.5	31.5%	1.9%
भारत	82.3	86.1	4.7%	2.3%
यूके	75.3	81.8	8.6%	2.3%
सऊदी अरब	77.8	80.3	3.3%	7.3%
यूक्रेन	64.9	64.7	-0.3%	34.5%

स्रोत: स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसआईपीआरआई) डेटाबेस

भारत का रक्षा उपकरण उद्योग

भारत इस तथ्य को समझता है कि रक्षा उपकरणों का विनिर्माण और संबद्ध तकनीकों का विकास एक कठिन और महंगा काम जरूर है, लेकिन यह राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश के रक्षा उपकरण उद्योग को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा अब स्वदेशीकरण पर फोकस बढ़ाया जा रहा है। इसके अंतर्गत देश की सरकारी और निजी कंपनियों, दोनों पर फोकस किया जा रहा है, ताकि अधिकतम रक्षा उपकरण भारत में ही तैयार किए जा सकें।

उत्पादन: विव 2016-17 से 2024-25 तक भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ी है। विव 2016-17 में देश का कुल रक्षा उत्पादन ₹ 740.5 बिलियन का था, जो विव 2024-25 तक बढ़कर ₹ 1.5 ट्रिलियन का हो गया। भारत के रक्षा उत्पादन क्षेत्र के विकास में सबसे बड़ी भूमिका सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने निभाई है। विव 2024-25 में कुल

उत्पादन में से लगभग 77.4% यानी ₹ 1166.1 बिलियन का योगदान सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और संयुक्त उद्यमों का रहा। इसके बाद निजी क्षेत्र ने लगभग ₹ 339.8 बिलियन का उत्पादन किया।

भारत का रक्षा संबंधी उत्पादन (बिलियन ₹ में)

वर्ष	रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के पुराने उपक्रम	रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के नए उपक्रम	अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के नए उपक्रम / संयुक्त उद्यम	रक्षा क्षेत्र की निजी कंपनियां	कुल उत्पादन
विव 2017	404.3	148.3	47.0	141.0	740.5
विव 2018	434.6	148.3	51.8	153.5	788.2
विव 2019	453.9	128.2	55.7	173.5	811.2
विव 2020	476.6	92.3	63.0	158.9	790.7
विव 2021	467.1	146.4	60.3	172.7	846.4
विव 2022	557.9	119.1	72.2	199.2	948.5
विव 2023	634.7	170.0	71.4	210.8	1086.8
विव 2024	744.3	195.5	67.7	266.8	1274.3
विव 2025	866.0	218.2	81.9	339.8	1505.9

स्रोत: रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय

भारत में रक्षा उत्पादन के अंतर्गत बख्तरबंद वाहन, भारी सैन्य वाहन, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर, युद्धपोत, मिसाइलें, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और भूमि समतलीकरण से संबद्ध उपकरण बनाए जाते हैं। विदेश व्यापार: हालिया कुछ वर्षों में भारत के रक्षा निर्यातों में तीव्र गति से प्रगति हुई है। विव 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात, पिछले वर्ष की तुलना में 12% की वृद्धि दर्ज करते हुए। 23,622 करोड़ तक पहुंच गए। विव 2024-25 में, भारत द्वारा हथियार, इनके विभिन्न सब-सिस्टम, संपूर्ण सिस्टम और अलग-अलग कलपुर्जे जैसे उत्पाद लगभग 80 देशों को निर्यात किए गए। विव 2028-29 तक भारत सरकार ने रक्षा निर्यात को ₹ 50,000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

भारत का रक्षा निर्यात (₹ करोड़ में) वर्ष

वर्ष	निजी कंपनियों को निर्यात का प्राधिकार	डीजीएफटी द्वारा जारी एससीओएमईटी	डीपीएसयू द्वारा कॉन्ट्रैक्ट मूल्य और अन्य निर्यात	कुल निर्यात
विव 2017	194.4	0.0	1327.5	740.5
विव 2018	3163.2	0.0	1519.2	788.2
विव 2019	9812.9	0.0	932.9	811.2
विव 2020	8007.8	203.0	904.7	790.7
विव 2021	7271.3	178.9	984.6	846.4
विव 2022	5965.0	6.7	6842.8	948.5
विव 2023	9050.8	351.3	6516.0	1086.8
विव 2024	13119.0	2090.4	5873.9	1274.3
विव 2025	13968.4	1264.3	8389.3	1505.9

स्रोत: रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय

¹ एसआईपीआरआई डेटाबेस

भारत के एयरोस्पेस उपकरणों के निर्यात में तीव्रता से वृद्धि हुई है। यह 2023 के 1.9 बिलियन यूएस डॉलर की तुलना में 2024 में 7.4 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। इसी दौरान आयात भी बढ़ा और यह 2023 के 11.8 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2024 में 12.6 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। भारत ने 2024 में 6.0 बिलियन यूएस डॉलर के पावर्ड विमानों का निर्यात किया, जबकि 11.7 बिलियन यूएस डॉलर का आयात किया। इससे पावर्ड विमान के व्यापार में 5.7 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार घाटा दर्ज हुआ। भारत द्वारा विमान के पुर्जा और स्पेसक्राफ्ट उपकरणों का 1.4 बिलियन यूएस डॉलर का निर्यात किया गया और 782.6 मिलियन यूएस डॉलर का आयात किया गया। इससे 601.8 मिलियन यूएस डॉलर का व्यापार अधिशेष रहा।

भारत के रक्षा उपकरण विनिर्माण और निर्यात क्षमताएं बढ़ाना:

आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने और वित्तीय वर्ष 2028-29 तक ₹3 ट्रिलियन का उत्पादन व ₹500 बिलियन का निर्यात लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत के रक्षा उपकरण उद्योग पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

- **संभावित देशों के साथ रणनीतिक सहयोग बढ़ाना:** अफ्रीका, मध्य पूर्व, यूरोप और दक्षिण व दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देशों में भारत के रक्षा उद्योग के लिए अब भी नए बाजार मौजूद हैं। भारत, सैन्य रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को रक्षा उपकरणों, उनके पुर्जा और सब सिस्टम/कंपोनेंट उप-प्रणालियों की आपूर्ति कर निर्यात अवसरों का लाभ उठा सकता है, क्योंकि जिन पुर्जा में श्रम अधिक लगता है उन्नत देश प्रायः विकासशील देशों से इनका आयात करते हैं। वहीं, भारत में विकासशील देशों को स्वदेशी रूप से विनिर्मित संपूर्ण प्रणालियां और रक्षा प्लैटफॉर्म प्रदान करने की क्षमता मौजूद है। तदनुसार, भारत अब विकासशील देशों को अन्य के साथ-साथ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, आकाश सर्फेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम जैसे अपने प्रमुख रक्षा उपकरण निर्यात करने के लिए नए करार करने पर बल दे सकता है। इसके साथ ही, भारत नौसेना क्षेत्र में भी अपना निर्यात बढ़ाने को प्राथमिकता दे सकता है। भारतीय नौसेना के ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स और ऑटोनॉमस अंडरवॉटर व्हीकल (एयूवी) जैसे उपकरणों की निर्यात संभावनाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा सकता है।
- **निर्यात सुगमीकरण को और बेहतर बनाना:** भारत इस समय निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना संबंधी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर काम कर रहा है, जिससे भारत के रक्षा निर्यातों को गति मिलेगी और इस उद्योग को समग्र सहयोग मिलेगा। इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए इस परिषद द्वारा कार्यशालाओं और सेमिनारों के जरिए क्षमता विकास पर फोकस किया जा सकता है और इस परिषद का उपयोग रक्षा व्यापार संबंधी जानकारी के लिए एक केंद्र के रूप में किया जा सकता है। भारतीय दूतावासों में निर्यात सहायता डेस्क स्थापित करना और डीपीएसयू, निजी विनिर्माता और रक्षा मंत्रालय जैसे घरेलू हितधारकों के बीच एक मजबूत व्यवस्था विकसित करने से इसकी भूमिका और भी सशक्त हो जाएगी।
- **वेंडर विकास कार्यक्रम तैयार करना:** रक्षा मंत्रालय द्वारा एक ऐसा विकास कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत भौतिक दौरा, इन्फ्रास्ट्रक्चर का मूल्यांकन, तकनीकी क्षमताओं, उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता नियंत्रण उपायों जैसे मानकों के आधार पर सुव्यवस्थित गुणवत्ता मूल्यांकन प्रक्रिया के जरिए संभावित आपूर्तिकर्ताओं की पहचान की जा सके, उनका मूल्यांकन किया जा सके और उनकी सूची तैयार की जा सके। चिह्नित संभावित वेंडरों को उनकी क्षमता के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में रखा जा सकता है और तैयार की गई यह सूची संबंधित हितधारकों को उपलब्ध कराई जा सकती है, ताकि वेंडर चयन के दौरान यह एक व्यापक और उपयोगी डेटाबेस के रूप में काम आ सके।
- **रक्षा क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए बजट बढ़ाना:** वर्ष 2021-22 में भारत के रक्षा संबंधी शोध एवं विकास पर कुल रक्षा बजट का केवल लगभग 5.9% व्यय किया गया, जो वैश्विक मानकों 10-15% से काफी कम है। इसके अलावा, केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के लिए निर्धारित राशि कुल रक्षा बजट के 4% से भी कम रही, जिसके लिए 2023-24 की रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने चिंता जताई थी। रक्षा मंत्रालय की शोध एवं विकास शाखा के रूप में डीआरडीओ की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, उसके अनुसंधान कार्यों के लिए बजट में वृद्धि करना बहुत आवश्यक है। इससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को और अधिक मजबूती मिलेगी।
- **दोहरे उपयोग वाली उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देना:** भारत के रक्षा उद्योग में शोध एवं विकास की गति में शिथिलता आई है। भारतीय रक्षा कंपनियों का शोध एवं विकास अनुपात केवल 1.2% है, जबकि वैश्विक औसत 3.4% है²। यह स्थिति स्पष्ट रूप से चिंतनीय है। रक्षा क्षेत्र में नवाचार बढ़ाने और संस्थाओं में सक्रिय और शोध एवं विकास का बेहतर परिवेश तैयार करने के क्रम में, सरकार द्वारा अन्य के साथ-साथ साइबर सुरक्षा, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन जैसी उभरती हुई अत्याधुनिक तकनीकों में शोध और निवेश बढ़ाने के लिए और अधिक कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- **रक्षा क्षेत्र-विशिष्ट वित्तपोषण कार्यक्रम तैयार करना:** वित्तीय संस्थाएं रक्षा क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों के लिए ऐसे विशेष वित्तपोषण संबंधी कार्यक्रम तैयार कर सकती हैं, जो उनकी अनोखी जरूरतों के अनुरूप हों। इनमें कैपेक्स-आधारित स्टार्टअप सहित शुरुआती चरण की कंपनियों को आवश्यक सहयोग दिया जा सकता है। वित्तीय संस्थाएं उन इनक्यूबेटरों के साथ साझेदारी कर सकती हैं जो रक्षा क्षेत्र के स्टार्टअप के साथ काम करते हैं, ताकि पात्र कंपनियों की पहचान कर उन्हें सही समय पर सहायता दी जा सके। अक्सर नवोद्यमों (स्टार्टअप) के पास संपूर्ण वित्तीय जानकारी नहीं होती और वे फंडिंग के समुचित विकल्पों तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में वित्तीय संस्थाएं वित्तीय परामर्शी सेवाएं देकर इस अंतर को कम कर सकती हैं। साथ ही, कंपनियां को उनका परिचालन बढ़ाने, शोध एवं विकास में निवेश करने या नए क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए, वित्तीय संस्थाएं इन कंपनियों को उनके विकास चक्र के अनुरूप दीर्घावधि ऋण उपलब्ध करा कर विकास वित्त प्रदान कर सकती हैं।
- **डिफेंस मूल उपकरण विनिर्माताओं द्वारा अपने आपूर्तिकर्ताओं को वित्तीय सहयोग बढ़ाना:** चूंकि रक्षा क्षेत्र के मूल उपकरण विनिर्माता अपने आपूर्तिकर्ताओं को सीमित वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, अतः सरकार द्वारा एक ऐसा अनुकूल ढांचा तैयार किया जा सकता है, जहां मूल उपकरण विनिर्माता बैंक के साथ मिलकर संरचित वित्तीय कार्यक्रम शुरू कर सकें। इससे आपूर्तिकर्ताओं की नकदी प्रवाह प्रबंधन के लिए दीर्घावधि भुगतान की शर्तें, गारंटी जैसी आवश्यकताएं पूरी होंगी। आमतौर पर, ऐसे मॉडल यूएसए जैसे देशों में अपनाए जाते हैं। कई महत्वपूर्ण तरीके हैं, जिनसे मूल उपकरण विनिर्माता अपने आपूर्तिकर्ताओं को वित्तीय सहयोग दे सकते हैं। इनमें आपूर्तिकर्ता ऋण कार्यक्रम, जहां मूल उपकरण विनिर्माता सीधे आपूर्तिकर्ताओं को ऋण उपलब्ध कराते हैं; उत्पादन आधारित प्रोत्साहन; रिवाॉल्विंग क्रेडिट लाइन्स; इक्विटी निवेश; और फैक्ट्रिंग संस्थानों के साथ मूल उपकरण विनिर्माताओं की फैक्ट्रिंग व्यवस्थाएं शामिल हैं। इससे मूल उपकरण विनिर्माताओं को भी बेहतर और विश्वसनीय आपूर्ति शृंखला का लाभ मिलता है। ■

² फास्ट इंडिया एवं आईआईएफएल सिक्वोरिटीज, स्टेट ऑफ इंडस्ट्री आरएंड डी इन इंडिया. 2024

वैश्विक एकीकरण और संरक्षणवादी उपायों के प्रभाव

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम् बैंक) द्वारा वर्ष 2016 में ब्रिक्स आर्थिक शोध वार्षिक सम्मान (ब्रिक्स सम्मान) की स्थापना की गई थी। ब्रिक्स सम्मान की स्थापना अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार, विकास एवं संबंधित वित्तपोषण के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। यह सम्मान विशेष रूप से ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के नागरिकों द्वारा विश्व के किसी भी विश्वविद्यालय तथा शैक्षणिक संस्था में प्रस्तुत संबंधित विषयों पर बेहतरीन शोधकार्य के लिए दिया जाता है। यह लेख "वैश्विक एकीकरण और संरक्षणवादी उपायों के प्रभाव" शीर्षक वाले डॉक्टरेट शोध प्रबंध पर आधारित है, जिसे इंडिया एक्जिम् बैंक के ब्रिक्स आर्थिक शोध वार्षिक सम्मान 2025 के लिए विजेता प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। यह शोध प्रबंध भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में सहायक सलाहकार डॉ. अनिर्बन सान्याल द्वारा लिखा गया है। डॉ. सान्याल ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलीफोर्निया सांता क्लूज़, यूएसए से 2023 में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की।

"वैश्विक गांव" (ग्लोबल विलेज) का विचार सबसे पहले 1964 में मशहूर मीडिया एवं संचार के विद्वान 'मार्शल मैकलुहान' ने दिया था। आज हम एक ऐसी वैश्विक अर्थव्यवस्था में जी रहे हैं, जहां व्यापार, पूंजी प्रवाह और तकनीक देशों को परस्पर जोड़ने का काम करती है। 1990 के बाद से अर्थव्यवस्थाओं के बीच शुरु हुए अभूतपूर्व आर्थिक एकीकरण को 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के संक्रामक-प्रभाव का कारण माना गया था (आईएमएफ, 2012)। इसके प्रभावों को कम करने के लिए अलग-अलग देशों द्वारा विभिन्न नीतिगत उपाय किए गए। घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए आयात शुल्क बढ़ाए गए (अंकटाड, 2013)। साथ ही, वैश्विक वित्तीय अनिश्चितताओं को कम करने के लिए पूंजी-नियंत्रण और अन्य मैक्रो-पूडेंशियल उपाय किए गए (कोरीनेक एवं सैंड्री, 2015)। इस शोध प्रबंध में अर्थव्यवस्था से जुड़े ऐसे ही नीतिगत उपायों के प्रभावों पर फोकस किया गया है। इस शोध प्रबंध में विशेष रूप से व्यापार पर टैरिफ के प्रभाव और अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह पर पूंजी-नियंत्रण उपायों के प्रभावों को रेखांकित किया गया है। इस शोध प्रबंध के अध्यायों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

इस शोध प्रबंध का पहला अध्याय, यूएस-चीन व्यापार युद्ध से भारत के लिए उत्पन्न व्यापार-विचलन के अनुभवजन्य साक्ष्यों पर पर केंद्रित है। यूएस और इसके अन्य व्यापार साझेदारों के बीच हालिया व्यापार विवाद के चलते यूएस व्यापार आयोग ने अन्य व्यापार साझेदारों पर उच्च टैरिफ लगा दिए। ये टैरिफ 2018 से 2020 के बीच लगाए गए। इनमें सबसे अधिक प्रभाव चीन से किए जाने वाले आयात पर पड़ा। चीन ने भी जवाब में यूएस के कई प्रमुख उत्पादों पर उच्च टैरिफ लगा दिए। इस स्थिति में भारत और इसके जैसे अन्य साझेदार देशों के लिए निर्यातों के नए अवसर खुल गए। इस अध्याय में, उच्च टैरिफ के चलते भारत पर व्यापार-विचलन के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है। इस विश्लेषण में भारत, यूएस और चीन के बीच 2017 से 2019 तक के विस्तृत उत्पाद-स्तरीय व्यापार आंकड़ों का उपयोग किया गया। व्यापार तीव्रता में औसत बदलाव का अनुमान डिफरेंस-इन-डिफरेंस पद्धति से लगाया गया। व्यापार युद्ध में लगाए गए शुल्क अल्पकालिक थे। इसलिए अलग-अलग उत्पादों में प्रतिस्थापन की क्षमता अलग होने के कारण व्यापार-तीव्रता पर औसत प्रभाव बहुत कम आंका जा सकता है। इसलिए उक्त मॉडल को और बेहतर बनाने के लिए इसमें संशोधन किया गया। अधिक सटीक ढांचा तैयार करने के क्रम में, इसमें उत्पाद-स्तर की भिन्नताओं को शामिल करते हुए तीन व्यापक उत्पाद वर्गीकरण अपनाए गए: (i) तैयार उत्पाद और मध्यवर्ती उत्पाद (ii) समान प्रकृति वाले उत्पाद और अलग प्रकृति वाले उत्पाद (iii) अत्यधिक लचीले और कम लचीले उत्पाद। यदि किसी वस्तु के निर्यात पर प्रतिबंध लगता है तो, ऐसे में किसी उत्पाद को पूरी तरह से तैयार करने के क्रम में इस्तेमाल होने वाले 'मध्यवर्ती उत्पादों' के लिए विकल्प मिल जाना बहुत मुश्किल है, जबकि 'तैयार उत्पाद' के लिए विकल्प मिलने में इतनी दिक्कतें नहीं आतीं। अतः यह माना जाता है कि व्यापार में विचलन की स्थिति

(टैरिफ, समझौते, प्रतिबंध आदि) होने पर कम समय में भी मध्यवर्ती उत्पादों की तुलना में तैयार उत्पादों का व्यापार तेजी से बढ़ता है। इसी प्रकार, विभेदित (डिफरेंशिएटेड) उत्पादों के लिए भी विकल्प मिलना मुश्किल होता है, इसलिए इनकी मांग कम लोचदार होती है यानी इनकी कीमत बदलते ही मांग भी बदल जाती है। प्रायोगिक निष्कर्षों के अनुसार चीन पर लगाए गए उच्च टैरिफ से भारत लाभान्वित हुआ है। निष्कर्ष बताते हैं कि चीन पर लगे उच्च टैरिफ का लाभ भारत को मिला। भारत से यूएस को निर्यात बढ़ गया। तथापि, चीन को भारत से किए गए निर्यात पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं दिखा। इस विश्लेषण में किए गए उल्लेख के अनुसार, यूएस ने चीन के जिन उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाया था, उनमें भारत के विनिर्माताओं के पास तुलनात्मक लाभ की स्थिति थी, तो वे इससे लाभान्वित हुए। लेकिन जवाब में चीन द्वारा अन्य के साथ-साथ सोयाबीन, कृषि उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उत्पाद लक्ष्य किए गए, इन क्षेत्रों में भारत लाभ नहीं ले पाया। आयात पर औसत प्रभाव सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं पाया गया। निष्कर्षों से पता चलता है कि भारत में व्यापार-विचलन उत्पाद-स्तर पर काफी भिन्न था। विशेष रूप से, भारत से यूएस को अंतिम उत्पादों, समान प्रकृति वाले उत्पादों और अत्यधिक लचीले उत्पादों का निर्यात अधिक बढ़ा।

दूसरे अध्याय में व्यापार नीति अनिश्चितता में आए बदलावों और एक संरचनात्मक मॉडल का उपयोग कर वैश्विक व्यापार प्रवाह पर पड़े प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। व्यापार युद्ध पर मिले हालिया दस्तावेजों से पता चला है कि यूएस और चीन के बीच बढ़े हुए टैरिफ के चलते व्यापार-विचलन का प्रभाव अलग-अलग देशों पर अलग-अलग स्तर का रहा। इसी दौरान, व्यापार-युद्ध की दिशा को लेकर स्पष्टता न होने की वजह से व्यापार नीति अनिश्चितता सूचकांक ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर पहुंच गया। शोधकर्ताओं ने इस विविधता का कारण व्यापार नीति अनिश्चितता में आए परिवर्तनों को माना है। इस अध्याय में वैश्विक व्यापार प्रवाह पर व्यापार नीति अनिश्चितता (टीपीयू) के प्रभाव को समझने का प्रयास किया गया है। इसके लिए बहु देश रिकार्डियन व्यापार मॉडल में इस अनिश्चितता को शामिल किया गया है। प्रस्तावित मॉडल ईटन और कोर्टम (2002) के बहु देश, बहु क्षेत्र वाले व्यापार मॉडल पर आधारित है, जिसमें अनिश्चितता का नया तत्त्व जोड़ा गया है। व्यापार नीति अनिश्चितता का तत्त्व दो स्रोतों से लिया गया है - पहला, व्यापार नीति बदलने की संभावना; और दूसरा, टैरिफ दरों के आकार को लेकर यादृच्छिक अनिश्चितता। व्यापार नीतियों में अनिश्चितता के चलते कीमतों में परिवर्तन आता है, जिससे मांग भी बदलती है। इन दोनों स्रोतों को इस्तेमाल करने की वजह यह है कि दुनिया में जब भी संरक्षणवाद बढ़ा है, तब ऐसे ही हालात देखने को मिले हैं, ब्रेक्सिट या यूएस व्यापार युद्ध इसके अच्छे उदाहरण हैं। ऐसी दोहरी अनिश्चितता का विचार ब्रेक्सिट और यूएस-चीन व्यापार युद्ध जैसी वास्तविक घटनाओं से लिया गया है। इन घटनाओं के दौरान अपनाई गई नीतियों ने व्यापार परिवेश में अनिश्चितता बढ़ा दी, क्योंकि व्यापार साझेदारों को

व्यापार नीतियों में संभावित परिवर्तनों के बारे में जानकारी नहीं थी और वे यह भी नहीं जानते थे कि ऐसे परिवर्तन व्यापार लागतों को कैसे प्रभावित करेंगे। व्यापार नीतियों में ऐसी अनिश्चितता उत्पादन की योजना बनाने में भारी समायोजन लागत के कारण व्यापार साझेदारों के लिए बड़ी चुनौतियां पैदा करती है। जब भविष्य की व्यापार नीति को लेकर स्पष्टता नहीं होती, तब व्यापार साझेदार अपनी उत्पादन योजनाएं बनाते हैं और उसी के अनुसार उत्पादन के संसाधनों का आवंटन करते हैं। तथापि, व्यापार नीतियां बाद के चरण में घोषित की जाती हैं, जब इन संसाधनों के आवंटन में परिवर्तन करना मुश्किल हो जाता है। इस मॉडल में व्यापार नीति की अनिश्चितता को इस तरह जोड़ा गया है कि हर देश यह अनुमान लगाता है कि आगे चलकर व्यापार नीति में परिवर्तन हो सकते हैं या नहीं। हर साझेदार यह सोचकर चलता है कि नीति बदलने की कितनी संभावना है और अगर बदली, तो टैरिफ कितना बढ़ या घट सकता है। क्योंकि टैरिफ और नीति बदलने की संभावना दोनों ही अनिश्चित हैं, इसलिए व्यापार साझेदार भविष्य की संभावित की मांग को लेकर अलग-अलग मूल्यांकन करते हैं। यही वजह है कि उनके आकलन उस वास्तविक टैरिफ (व्यापार नीति के घोषित होने के बाद सामने आने वाले टैरिफ) परिदृश्य से बहुत अलग निकल सकते हैं। इस मॉडल के जरिए यह समझने का प्रयास किया गया है कि व्यापार नीति में अनिश्चितता अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है। इसमें सैद्धांतिक तरीके से उल्लेख किया गया है कि अलग-अलग देशों के व्यापार साझेदारों में भविष्य की व्यापार नीति को लेकर जो अनुमान और संदेह होते हैं, वही तय करते हैं कि व्यापार किस दिशा में जाएगा या इसमें किस तरह के परिवर्तन होंगे। इन धारणाओं के आधार पर इस मॉडल में यह भी उल्लेख किया गया है कि किन-किन परिस्थितियों में व्यापार डायवर्जन कितना हो सकता है और उसका क्या परिदृश्य है। इसके बाद इसी सैद्धांतिक मॉडल को असली डेटा के अनुसार ढालकर पूरे पैमाने पर लागू किया जाता है, जिसमें दो चरणों की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस दौरान अलग-अलग टैरिफ दरों और नीति में बदलाव की अलग-अलग संभावनाओं वाले कई परिदृश्यों में व्यापार नीति की अनिश्चितता को मापा जाता है। अंत में, पूरा मॉडल इस बात का भी उल्लेख करता है कि व्यापार में इसी तरह की अनिश्चितता अन्य बाह्य कारणों से भी पैदा हो सकती है, जैसे चीन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन से अचानक दुनिया भर का व्यापार प्रभावित हो गया था।

तीसरे अध्याय में यह विश्लेषण किया गया है कि पूंजी नियंत्रण विभिन्न क्षेत्रों में सकल पूंजी प्रवाह को कैसे प्रभावित करता है। पूंजी नियंत्रण ऐसे नीतिगत उपाय होते हैं, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अचानक आने वाले पूंजी प्रवाह के उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए अपनाए जाते हैं। इसमें अक्सर विदेशी निवेश पर कर लगाना, बाहर से आने वाले निवेश की मात्रा को सीमित करना, या विदेशी निवेश से जुड़े कानूनी नियम सख्त करना जैसे उपाय शामिल होते हैं। आमतौर पर विकसित देश, अधिक आय की तलाश में उभरती अर्थव्यवस्थाओं में निवेश करते हैं, लेकिन जैसे ही निवेश का परिवेश कुछ बिगड़ने लगता है, तभी निवेश की पूंजी का रुख अचानक बदलकर वापस विकसित देशों या अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की ओर हो जाता है। विदेशी पूंजी के इस तरह अचानक वापस चले जाने से उभरती अर्थव्यवस्थाओं की स्थानीय मुद्रा पर दबाव बढ़ जाता है, व्यापार संतुलन बिगड़ जाता है, कर्ज का बोझ बढ़ जाता है और उनकी विकास क्षमताएं भी अस्थिर हो जाती हैं। 1990 के दशक में अधिकतर लैटिन अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशिया की अर्थव्यवस्थाओं को तीव्र और अस्थिर विदेशी पूंजी के आने-जाने के कारण गंभीर मुद्रा संकटों का सामना करना पड़ा। इसके जवाब में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं को विदेशी पूंजी के उतार-चढ़ाव से घरेलू अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पूंजी नियंत्रण यानी पूंजी पर नियंत्रण जैसी नीतियां अपनाने का परामर्श दिया। पूंजी नियंत्रण को मैक्रो-प्रूडेंशियल के रूप में उपयोग किया जाता है, इसका साधारण-सा उद्देश्य है- विदेशी पूंजी प्रवाह से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना। इन नियंत्रणों के प्रभाव

को कई पहलुओं पर परखा गया है। एक तरफ इनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना होता है, वहीं दूसरी तरफ निवेशक अक्सर ऐसी नीतियों के अनचाहे अप्रत्यक्ष प्रभावों का भी उल्लेख करते हैं। फोर्ब्स एट. अल. डफोर्ब्स और अन्य (2016) में प्रकाशित एक सर्वेक्षण में यह उल्लिखित है कि जब कोई देश पूंजी नियंत्रण संबंधी नीतियां अपनाता है, तो यह परिवर्तन दुनिया भर के निवेशकों को एक तरह का संकेत देता है कि देश की अर्थव्यवस्था में कुछ परिवर्तन या चिंता की स्थिति हो सकती है। यह "संकेत देने वाला प्रभाव" अक्सर उस नीति के असली उद्देश्य के साथ मिलकर काम करता है और फिर विविध क्षेत्रों के पूंजी प्रवाह को अलग-अलग तरह से प्रभावित कर सकता है। हमारे आर्थिक तंत्र यानी सरकार, बैंक और निजी कंपनियों के जोखिम उठाने के तरीके भी अलग-अलग होते हैं। इसलिए निवेशक भी अपनी पूंजी इन क्षेत्रों में इसी जोखिम के आधार पर बांटते हैं। जब उन्हें देश की आर्थिक स्थिति के बारे में कोई संकेत मिलता है, तो वही संकेत इन सभी क्षेत्रों में पूंजी के प्रवाह को अलग-अलग तरह से प्रभावित कर सकता है। यानी, एक ही नीति का असर हर जगह एक जैसा नहीं होता, कहीं ज़्यादा, कहीं कम, और कहीं बिलकुल अलग होता है।

इसके साथ ही, पूंजी नियंत्रण का प्रभाव अलग-अलग देशों और अलग-अलग क्षेत्रों में क्यों और कैसे विषम होता है, इसे समझने के लिए इस शोध प्रबंध के फ्रेमवर्क को और बढ़ाया गया। इसके लिए 15 देशों के विभिन्न क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह के बड़े डेटासेट का उपयोग किया गया। पूंजी नियंत्रण का सीधा प्रभाव यह बताता है कि जब किसी देश में यह नीति लागू होती है तो सरकार, बैंक और निजी कंपनियों जैसे क्षेत्रों के पूंजी प्रवाह पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरी तरफ, स्पिलओवर प्रभाव इस बात से तय होता है कि एक देश में लगाए गए पूंजी प्रतिबंध कैसे दुनिया के दूसरे देशों के पूंजी प्रवाह को प्रभावित करते हैं। इस अध्याय में पहले ऐसे संभावित "संकेत देने वाला प्रभावों" को समझाने के लिए एक सैद्धांतिक आधार दिया गया है। इसके बाद, इन विचारों को परखने के लिए दुनिया के विभिन्न देशों के क्षेत्र-स्तर के पूंजी प्रवाह के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है, ताकि यह देखा जा सके कि अलग-अलग क्षेत्रों में इसका प्रभाव कितना विषम होता है। सबसे पहले, पूंजी नियंत्रण के इस "संकेत देने वाले प्रभाव" को एक मल्टी-कंट्री (बहु-राष्ट्र) पोर्टफोलियो मॉडल में जोड़ा गया है। इस मॉडल में दिखाया गया है कि जब कोई देश विदेशी पूंजी पर कर बढ़ाता है, तो उसका प्रभाव केवल उसी देश के पूंजी प्रवाह पर नहीं पड़ता, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के पूंजी प्रवाह को भी प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि सीधा प्रभाव और स्पिलओवर प्रभाव दोनों ही हर क्षेत्र में एक समान नहीं होते। निवेशक जब किसी देश में पूंजी नियंत्रण बढ़ते हुए देखते हैं, तो वे इसे एक "संकेत" मानते हैं और इसी के अनुसार उनके निर्णय भी बदल जाते हैं। नतीजा यह होता है कि सरकार, बैंक और निजी कंपनियों जैसे क्षेत्रों में पूंजी प्रवाह विषम हो जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी नियंत्रण के प्रभाव में जो विषमता दिखाई देती है, उसे परखने के लिए इस शोध प्रबंध में 'स्पेशल रिग्रेशन' मॉडल का उपयोग किया गया। इसके लिए विभिन्न देशों के संस्थागत क्षेत्रों यानी सरकार, बैंक और निजी कंपनियों के तिमाही पूंजी प्रवाह के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। शोध अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि किसी देश में किए गए पूंजी नियंत्रण का सीधा असर मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र पर होता है। यानी विदेशी निवेशक सरकार से जुड़े बॉन्ड या सरकारी निवेश साधनों में पैसा लगाना कम कर देते हैं। इसके विपरीत, कॉर्पोरेट सेक्टर में आने वाली पोर्टफोलियो पूंजी पर घरेलू पूंजी नियंत्रण का लगभग कोई असर नहीं दिखाई देता। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी स्थिति अलग होती है। जब एक देश पूंजी पर नियंत्रण बढ़ाता है, तो इसका प्रभाव दूसरे देशों में दिखता है। इसके कारण दूसरे देशों के सभी सेक्टरों में निवेश बढ़ने लगता है। निवेशक अपने पैसे को उस देश से हटाकर अन्य सुरक्षित देशों की ओर ले जाते हैं, जिससे उन देशों में पूंजी का प्रवाह बढ़ जाता है। ■

इंडिया एक्जिम बैंक की ऋण-व्यवस्थाएं

सौजन्य : ऋण-व्यवस्था समूह

भारत सरकार ने अन्य के साथ-साथ विशेष रूप से विकासशील देशों के साथ भारत के व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2003-04 के आम बजट के जरिए भारत विकास पहल (आईडीआई) की शुरुआत की थी। इसे बाद में भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आयडियाज) नाम दिया गया। इस योजना का उद्देश्य विदेश में भारत के रणनीतिक, राजनैतिक और आर्थिक हित को बढ़ावा देना है। इस तरह भारत विकासशील देशों के साथ क्षमता विकास और कौशल हस्तांतरण, व्यापार तथा बुनियादी ढांचे के विकास के जरिए अपने विकास अनुभव साझा करता है और उभरती आर्थिक शक्ति और निवेशक देश तथा विकासशील देशों के लिए एक सहभागी के रूप में काम करता है। बैंक पॉलिस्सी संस्था के रूप में इस 'आइडियाज' योजना के अंतर्गत दूसरे देशों को प्रदत्त ऋण व्यवस्थाओं के लिए वित्तपोषण के एक माध्यम का काम करता है।

नवीनतम 'आयडियाज' दिशानिर्देश संशोधित किए गए हैं। ये 31 मार्च, 2022 से प्रभावी हैं। संशोधित 'आयडियाज' दिशानिर्देशों के अंतर्गत, अब भारत सरकार की रियायती वित्तपोषण योजना (सीएफएस) भी इस योजना का हिस्सा है। इसमें भारत सरकार रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण विदेशी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वाली भारतीय इकाइयों को सहयोग करने के लिए ऋण सहायता लेने वाली किसी भी सरकार या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली इकाई को रियायती वित्तपोषण प्रदान करती है। यह वित्त तब प्रदान किया जाता है, जब उक्त भारतीय इकाई ऐसी किसी विदेशी इकाई द्वारा टेंडर की गई परियोजना के निष्पादन का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त कर लेती है। इस वित्तपोषण के लिए पात्र परियोजना का रणनीतिक महत्त्व भारत सरकार द्वारा मामले वार आधार पर तय किया जाता है।

भारत सरकार द्वारा संप्रभु सरकारों या उनकी नामित एजेंसियों को दी जाने वाली ऋण-व्यवस्थाएं वित्तीय वर्ष 2003-04 से भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। ऋण-व्यवस्थाएं भारतीय निर्यातकों को नए भौगोलिक क्षेत्रों में प्रवेश करने या मौजूदा निर्यात बाजारों में अपने व्यवसाय को बढ़ाने में सहायक हैं और वह भी विदेशी आयातकों से बिना किसी भुगतान जोखिम के। बैंक भारतीय निर्यातकों के लिए किसी बाजार में प्रवेश के एक प्रभावी माध्यम के साथ-साथ बाजार विविधीकरण के साधन के रूप में ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करने पर विशेष जोर देता है। ये ऋण-व्यवस्थाएं सहभागी देशों को बड़े पैमाने पर जटिल परियोजनाओं (भारत से परियोजना निर्यात) के लिए प्रदान की जा रही हैं।

एक्जिम बैंक संप्रभु सरकारों, विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों और नामित सरकारी विदेशी संस्थाओं को ऋण-व्यवस्थाएं (एलओसी) प्रदान करता है। ये ऋण-व्यवस्थाएं उन देशों में खरीदारों को भारत से विकास और बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं, उपकरणों, वस्तुओं और सेवाओं के आयात के लिए प्रदान की जाती हैं। ऋण-व्यवस्थाएं किसे दी जाएंगी, उसकी राशि, शर्तें और उसके उद्देश्य का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। वहीं, एक्जिम बैंक भारत सरकार के

परिचालन माध्यम के रूप में इन ऋण-व्यवस्थाओं का वित्तपोषण, संचालन और निगरानी करता है।

एक्जिम बैंक इन ऋण-व्यवस्थाओं के तहत एफओबी/सीएफआर/सीआईएफ/सीआईपी आधार पर भारतीय निर्यातकों को कॉन्ट्रैक्ट मूल्य के 100% की प्रतिपूर्ति करता है, बशर्ते कि कुल कॉन्ट्रैक्ट मूल्य के कम-से-कम 75% (मामले- वार आधार पर 10% की छूट दी जा सकती है) माल एवं सेवाओं (परामर्श सेवाओं सहित) का आयात भारत से किया गया हो। इन ऋण-व्यवस्थाओं के जरिए उभरते बाजारों में भारत की परियोजना निष्पादन क्षमता को प्रदर्शित करने में भी मदद मिली है। इसके अलावा इन ऋण-व्यवस्थाओं ने हाल के वर्षों में विशेष रूप से अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशिआनिया और सीआईएस क्षेत्र के विकासशील देशों में गति पकड़ी है। इन ऋण-व्यवस्थाओं ने भारत के राजनैतिक, रणनीतिक और वाणिज्यिक हितों को बढ़ावा देने के साथ ही लाभार्थी देशों में भारत की राजनीतिक ख्याति और सद्भाव को बढ़ाने का भी काम किया है। साथ ही, ऋण-व्यवस्थाएं भारत की बढ़ती आर्थिक सुदृढ़ता के साथ-साथ प्राप्तकर्ता विकासशील देशों में बुनियादी ढांचागत विकास और क्षमता विकास में योगदान देने की भारत प्रतिबद्धता को वैश्विक पटल पर लाने में भी मददगार हैं। भारतीय निर्यातक अपने माल के लिए एक्जिम बैंक से पात्र मूल्य हासिल कर सकते हैं। भारतीय निर्यातक माल के शिपमेंट पर एक्जिम बैंक के जरिए पूरा भुगतान ले सकते हैं और इसमें उन्हें क्रेता या क्रेता देश से जुड़े किसी तरह के जोखिम का सामना नहीं करना पड़ता।

बैंक द्वारा यथा 31 सितंबर, 2025 को अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ओशिआनिया और सीआईएस के 62 से अधिक देशों को 26.12 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक और ₹ 4850 करोड़ (मालदीव सरकार को रुपये मूल्यवर्ग वाली अम्ब्रेला ऋण-व्यवस्था से संबंधित) की ऋण प्रतिबद्धता के साथ 288 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान जा चुकी हैं, जो भारत से निर्यातों के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध हैं। इस प्रकार, ऋण-व्यवस्थाएं भारत से परियोजनाओं, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के संवर्धन एवं सुगमीकरण के लिए प्रभावी साधन हैं।

इंडिया एक्जिम बैंक की ऋण-व्यवस्थाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपर्क कीजिए :

श्रीमती कुसुम सिंह,

उप महाप्रबंधक,

ऑफिस ब्लॉक, टावर 1, 7वीं मंजिल

एड्जेंसेंट सिंग रोड, किदवई नगर (पूर्व)

नई दिल्ली 110023

नई दिल्ली-110023, फोन: (011) 24607700

ईमेल: eximloc@eximbankindia.in ■

दास्तान-ए-कामयाबी

इंडिया एक्जिम बैंक द्वारा भारत सरकार के सहयोग से गयाना सरकार को प्रदत्त 23.37 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था।

परियोजना विवरण:

बैंक ने भारत की एकमात्र विमान निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) से हिंदुस्तान 228-201 के दो विमानों की खरीद के लिए गयाना सरकार को भारत सरकार समर्थित 23.37 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की है। इस आपूर्ति करार के अंतर्गत एचएएल द्वारा गयाना रक्षा बल को दो विमानों के साथ-साथ ग्राउंड हैंडलिंग उपकरण (जीएचई), ग्राउंड सपोर्ट उपकरण (जीएसई), तकनीकी प्रकाशन, विनिर्माता द्वारा सुझाए गए स्पेयर पार्ट्स (एमआरएलएस) आदि भी उपलब्ध कराना शामिल है।

परियोजना की कुल लागत - 23.37 मिलियन यूएस डॉलर

पूरी हुई परियोजना: इस ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत पूरी राशि का उपयोग कर लिया गया है और करार में उल्लिखित अनुसार दो विमानों, उनके सभी उपकरणों और स्पेयर पार्ट्स सहित सभी सामग्री सफलतापूर्वक गयाना रक्षा बल को पहुंचा दी गई है। गयाना सरकार ने भारत द्वारा की गई इन सभी आपूर्तियों को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। यह परियोजना सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है और दोनों विमानों को 18 नवंबर, 2024 को आधिकारिक रूप से गयाना रक्षा बल (जीडीएफ) वायुसेना (एयर कॉर्प्स) में शामिल कर लिया गया है।



रविवार को विमानों के लॉन्च के दौरान गयाना के माननीय प्रधानमंत्री श्री मार्क फिलिप्स के साथ गयाना में भारत के उच्चायुक्त श्री अमित तेलंग, मंत्रिमंडल के सदस्य और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

तिमाही गतिविधियां

सौजन्य : कॉर्पोरेट संचार समूह

इंडिया एक्विजिमेंट बैंक ने की ब्रिक्स आर्थिक शोध वार्षिक सम्मान 2025 के विजेता की घोषणा

वर्ष 2016 में ब्रिक्स फोरम की अध्यक्षता भारत ने की थी और उसी साल इंडिया एक्विजिमेंट बैंक द्वारा ब्रिक्स अंतरबैंक सहयोग तंत्र की अध्यक्षता की गई थी। मार्च 2016 में ही इंडिया एक्विजिमेंट बैंक द्वारा ब्रिक्स आर्थिक शोध वार्षिक सम्मान की स्थापना की गई थी। इस सम्मान का उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए अर्थशास्त्र से संबंधित प्रासंगिक विषयों पर शोध को बढ़ाना और प्रोत्साहन देना है। इंडिया एक्विजिमेंट बैंक के ब्रिक्स आर्थिक शोध वार्षिक सम्मान 2025 के विजेता की घोषणा कर दी गई है। डॉ. अनिर्बन सान्याल को इसका विजेता घोषित किया गया है। इसकी घोषणा ब्राज़ीलियन डेवलपमेंट बैंक (बीएनडीईएस) द्वारा रियो डि जेनेरो में 08 जुलाई, 2025 को ब्रिक्स अंतरबैंक सहयोग व्यवस्था (आईसीएम) की 15वीं वार्षिक बैठक के दौरान की गई। इस दौरान ब्रिक्स आईसीएम के सदस्य विकास बैंकों के प्रमुख भी उपस्थित रहे।

इस वार्षिक बैठक के दौरान, ब्रिक्स अंतरबैंक सहयोग व्यवस्था के सदस्य विकास बैंकों अर्थात् ब्राज़ीलियन डेवलपमेंट बैंक (बीएनडीईएस); स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (वीईबी.आरएफ); चाइना डेवलपमेंट बैंक (सीडीबी); इंडिया एक्विजिमेंट बैंक और डेवलपमेंट बैंक ऑफ़ सदरन अफ्रीका (डीबीएसए) के प्रमुख उपस्थित रहे। इस फोरम के दौरान, इंडिया एक्विजिमेंट बैंक की प्रबंध निदेशक, सुश्री हर्षा बंगारी और बीएनडीईएस के अध्यक्ष, श्री अलोइज़ियो मेर्कादेंते ओलिवा ने इस डॉक्टरल थीसिस पर आधारित बैंक के प्रासंगिक आलेख "वैश्विक एकीकरण और संरक्षणवादी उपायों का प्रभाव" का भी विमोचन किया।

भारत-ब्राज़ील द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अपार अवसर: एक्विजिमेंट बैंक का शोध अध्ययन

ब्राज़ील के साओ पाउलो में 10 जुलाई, 2025 को एक्विजिमेंट बैंक के "सस्टेनेबल सहयोग के जरिए भारत-ब्राज़ील आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करना" शीर्षक वाले शोध अध्ययन का विमोचन किया गया। इसका विमोचन साओ पाउलो में भारत के महावाणिज्य दूत, श्री हंसराज सिंह वर्मा और एक्विजिमेंट बैंक की प्रबंध निदेशक, सुश्री हर्षा बंगारी द्वारा ब्राज़ील में एक्विजिमेंट बैंक के नए प्रतिनिधि कार्यालय में किया गया। लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र में यह एक्विजिमेंट बैंक का पहला प्रतिनिधि कार्यालय है। इसका उद्घाटन 24 जून, 2025 को भारत सरकार की माननीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारामन द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया था। यह उद्घाटन नई दिल्ली में 'निर्यात वृद्धि से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि' थीम पर आयोजित एक्विजिमेंट बैंक के ट्रेड कॉन्क्लेव के दौरान किया गया।

भारत और ब्राज़ील के बीच रणनीतिक साझेदारी है और दोनों देशों के साझा हितों को ध्यान में रखते हुए इस शोध अध्ययन में व्यापार के अलावा परस्पर लाभ के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं का भी उल्लेख किया गया है। इनमें डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल भुगतान प्रणाली, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, शोध एवं तकनीकी नवाचार सहित विशेष रूप से जैव ईंधन, संपोषी व अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इस शोध अध्ययन में सुझाया गया है कि व्यापार और निवेश को बढ़ाने की संभावनाओं को भुनाने के लिए भारत-मर्कोसुर

तरजीही व्यापार करार का दायरा बढ़ाकर इसे मुक्त व्यापार करार में परिवर्तित करने पर विचार किया जा सकता है।

इंडिया एक्विजिमेंट बैंक ने भारत सरकार को अंतरित किया ₹325 करोड़ का निवल लाभ शेष

माननीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारामन को ₹ 325 करोड़ के निवल लाभ शेष के अंतरण की रसीद प्रस्तुत करती एक्विजिमेंट बैंक की प्रबंध निदेशक, सुश्री हर्षा बंगारी और दोनों उप प्रबंध निदेशक, श्री तरुण शर्मा और सुश्री दीपाली अग्रवाल। इस अवसर पर वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव श्री एम. नागराजू विशेष रूप से उपस्थित रहे।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने प्रमुख व्यावसायिक कार्यनिष्पादन पैरामीटरों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। यह वृद्धि भारत के व्यापार और निवेश तथा सहभागी देशों की विकास प्राथमिकताओं को सहायता प्रदान करने की बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक का निवल लाभ ₹3243 करोड़ का रहा, जिसमें गत वर्ष की तुलना में 29% की वृद्धि दर्ज की गई। बैंक द्वारा चुकता पूंजी पूरी तरह भारत सरकार द्वारा सब्सक्राइब की गई है।

ईडीबी-इंडिया एक्विजिमेंट बैंक द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित वेबिनार में रेखांकित की गई भारत और मध्य एशिया आर्थिक सहयोग के जरिए परस्पर तालमेल और व्यापार वित्त की संभावनाएं

यूरोशियन डेवलपमेंट बैंक और इंडिया एक्विजिमेंट बैंक ने क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। दोनों संस्थाओं ने मिलकर 10 सितंबर, 2025 को एक संयुक्त वेबिनार का आयोजन किया। दोनों संस्थाओं के बीच यह पहली साझी पहल है। यह वेबिनार, भारत और मध्य एशियाई क्षेत्र के बीच आर्थिक और वित्तीय संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक रणनीतिक प्रयास है। इस सहयोग का उद्देश्य व्यापार, निवेश और विकास वित्त जैसे क्षेत्रों में परस्पर तालमेल बढ़ाना और दोनों क्षेत्रों की आर्थिक साझेदारी को नए आयाम देना है।

यूरोशियन डेवलपमेंट बैंक (ईडीबी) यूरोशिया में निवेश करने वाला एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। पिछले 19 वर्षों से यह बैंक अपने सदस्य बैंकों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने, आपसी संबंधों को सुदृढ़ बनाने तथा समग्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रहा है। जुलाई 2025 तक ईडीबी के संचयी पोर्टफोलियो में 19.1 बिलियन यूएस डॉलर के निवेश के साथ 319 परियोजनाएं शामिल हैं। इनके पोर्टफोलियो में मुख्य रूप से ऐसी परियोजनाएं शामिल हैं, जिनका प्रभाव समेकित रूप से परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल प्रणालियों, हरित ऊर्जा, कृषि, विनिर्माण और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों पर पड़ता है। यह बैंक अपने परिचालनों में संयुक्त राष्ट्र के संपोषी विकास लक्ष्यों और ईएसजी सिद्धांतों का पालन करता है। ईडीबी अपनी 2022-2026 रणनीतिक अंतर्गत तीन मेगा-परियोजनाओं का निष्पादन कर रहा है। ■

विभिन्न देशों का आर्थिक परिदृश्य (जून 2025)

सौजन्य: शोध एवं विश्लेषण समूह

नेपाल



सितंबर 2025 की शुरुआत में नेपाल में जेन ज़ी ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए। इन प्रदर्शनों की मुख्य वजह थी कि नेपाल सरकार ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में समय पर पंजीकरण न होने के कारण 26 सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया। यह आंदोलन जेन ज़ी के युवाओं द्वारा शुरू किया गया, जो लंबे समय से सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार और असमानता से नाराज थे। समय के साथ यह विरोध हिंसक हो गया और अंततः प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद सरकार भंग कर दी गई। पहली बार नेपाल में एक महिला अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त हुईं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमंत्री के रूप में मार्च 2026 तक देश का नेतृत्व करेंगी। आर्थिक दृष्टि से नेपाल की अर्थव्यवस्था लगभग 43 बिलियन यूएस डॉलर की है और पिछले साल के 3.6% के मुकाबले 2025 में निजी खर्च और रैमिटेन्स से इसके 4.3% तक बढ़ने का अनुमान है, जो पर्यटन से इस वृद्धि को गति मिलने की उम्मीद है, हालांकि वैश्विक अनिश्चितताएं जोखिम पैदा कर सकती हैं। मुद्रास्फीति लगभग 3.4% रहने की संभावना है, जो वैश्विक कमोडिटी कीमतों और भारतीय रुपये के प्रदर्शन से प्रभावित होगी। 1994 से अब तक नेपाली रुपया एनपीआर 1.6=₹1 की विनिमय दर से भारतीय रुपये के साथ स्थिर है। रैमिटेन्स के कारण चालू खाता अधिशेष में है और 2025 में यह जीडीपी का लगभग 4.3% रहेगा।

सेनेगल



सेनेगल, पश्चिम अफ्रीका का एक स्थिर देश है। यहां राष्ट्रपति बसीरू डियोमाये फेय के नेतृत्व में राजनीतिक परिवेश स्थिर है। 2024 में देश की अर्थव्यवस्था लगभग 33.8 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गई और भावी वर्षों में यानी 2025 से 2029 तक इसके तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। इस विकास का आधार तेल और गैस का निर्यात, बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विस्तार और व्यापार को बढ़ावा देने वाले सुधार हैं। अच्छे मौसम और सरकारी मदद मिलने के चलते कृषि क्षेत्र में भी विस्तार होने की संभावना है। तेल से संबद्ध गतिविधियों के कारण, सेवा क्षेत्र में, विशेषकर व्यापार, परिवहन और वित्त में लाभ होने की उम्मीद है। मुद्रास्फीति 2024 में 0.8% थी और 2025 में इसके घटकर 0.7% तक रहने का अनुमान है। इसका कारण है, वैश्विक कमोडिटी की कम होती कीमतें, सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी और यूएस डॉलर के मुकाबले मजबूत होती देश की मुद्रा सीएफए फ्रैंक, जिसकी विनिमय दर 1 यूएस डॉलर के मुकाबले 588.3 सीएफए फ्रैंक है। तथापि, सेनेगल राजकोषीय घाटा पूरा करने के लिए घरेलू और बाह्य कर्ज पर निर्भर है। मार्च 2025 की आईएमएफ रिपोर्ट में देश के कमजोर बजट नियंत्रण और वित्तीय पारदर्शिता पर चिंता जताई गई है, जिसका संज्ञान लेते हुए सरकार ने इन क्षेत्रों में सुधार करना शुरू किया है। 2025 के बजट में मंत्रालयों के खर्च में 9% की कटौती और संस्थागत सुधार शामिल हैं। सार्वजनिक ऋण 2024 में जीडीपी का 125.7% रहा, जिससे देश मध्यम स्तर के ऋण संकट के जोखिम में है। तथापि, राजनीतिक अस्थिरता या सामाजिक अशांति बढ़ती है, तो डिफॉल्ट (ऋण न चुका पाने) का खतरा मध्यम अवधि में बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसे में सरकार जरूरी लेकिन सख्त वित्तीय कदम उठाने से पीछे हट सकती है।

फ्रांस



फ्रांस यूरोपीय संघ की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी शक्ति सेवाओं, एरोनॉटिक्स और लग्जरी उत्पादों में है। हालिया श्रम, कर और पेंशन सुधारों से प्रतिस्पर्धा बेहतर हुई है, तथापि राजनीतिक अस्थिरता के चलते कुछ अवरोध पैदा होने की भी आशंका है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने 09 सितंबर को सेबास्टियन लेकोनू को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, क्योंकि फ्रांस्वा बेयरु 2026 के बजट पर अविश्वास प्रस्ताव में हार गए थे। लेकोनू को बिना बहुमत वाली बिखरी संसद का सामना करना पड़ रहा है। यहां के वामपंथी और दक्षिणपंथी, दोनों ही उनके विरोध में हैं। इससे सरकार जल्दी गिरने का खतरा और कानून बनाने में मुश्किलें बढ़ गई हैं। वित्तीय स्थिति भी तनावपूर्ण है। 2024 में सार्वजनिक ऋण जीडीपी का लगभग 113% और राजकोषीय घाटा 5.8% रहा, और 2026 से पहले इसमें सुधार की उम्मीद कम ही है। वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2024 के 1.1% से घटकर 2025 में 0.7% तक रह जाने का अनुमान है, जो यूरो-ज़ोन औसत से पीछे है। हालांकि 2029 तक मांग बढ़ने पर धीरे-धीरे इसके 1.6% तक पहुंच जाने की संभावना है। मुद्रास्फीति 2024 के 2.3% से घटकर 2025 में 1% तक रहने की संभावना है और 2029 तक औसतन 1.8% हो जाने की संभावना है, क्योंकि घरेलू कीमतों पर दबाव कम है। इसी बीच, अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव और यूरो-ज़ोन में निवेश बढ़ने से यूरो मजबूत रहेगा। 2025-26 में इसके औसतन लगभग 1.15 यूएस डॉलर : 1 यूरो पर स्थिर रहने का अनुमान है, जिसके इस दशक के अंत तक 1.12 यूएस डॉलर : 1 यूरो तक आने की संभावना है।

जिबूती



जिबूती की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सेवाओं पर आधारित है, खासकर पुनः-निर्यात और इथियोपिया से जुड़े लॉजिस्टिक्स पर। यही वजह है कि यह क्षेत्रीय और वैश्विक व्यापार में बदलावों के प्रति संवेदनशील है। 2024 में तेजी से बढ़ने के बाद, 2025 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 5.2% और 2026 में 5.4% रहने का अनुमान है। यह गति 2024 में असाधारण बंदरगाह राजस्व के प्रभाव के कारण धीमी हो गई है। मुद्रास्फीति बेहद कम है। 2025 में, इसमें लगभग 0.6% तक की गिरावट की संभावना है, क्योंकि बाह्य कीमतों का दबाव घट रहा है। जिबूती फ्रैंक 177.7 प्रति 1 यूएस डॉलर के साथ स्थिर है, इसलिए विनिमय दर स्थिर रहती है। यद्यपि, चालू खाता अधिशेष जीडीपी के 10% से ज्यादा है, जो विदेशी सैन्य ठिकानों से मिलने वाले शुल्क से मजबूत हुआ है। तथापि, देश के सामने गंभीर ऋण चुनौतियां हैं। चायना एक्जिम बैंक को ऋण चुकौती संबंधी भुगतान की किस्तों पर मॉरिटोरियम के अंतर्गत 2028 तक रोक लगा दी गई है। इस संबंध में वार्ताएं जारी हैं, ताकि पुराने बकाया को पुनर्संरचित किया जा सके, ब्याज दरों में बदलाव हो और भुगतान की अवधि बढ़ाई जा सके। इसी तरह दूसरे सबसे बड़े ऋणदाता, भारत और पैरिस क्लब के देशों के साथ भी चर्चा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके परिणाम 2025 के अंत तक मिलने की उम्मीद है। विदेशी मुद्रा भंडार औसतन चार महीने के आयात को कवर कर सकता है और बहुपक्षीय वित्तीय मदद से इन्फ्रास्ट्रक्चर को सहयोग मिलेगा। लेकिन आईएमएफ और अन्य ऋणदाताओं का निरंतर सहयोग न मिले तो देश पर ऋण संकट का बड़ा जोखिम बना रहेगा। ■

मुद्राओं की स्थिति

सौजन्य : ट्रेजरी एवं लेखा समूह

जापानी येन

NRs

परंपरागत रूप से जापानी येन की विनिमय दर यूएस और जापान की ब्याज दरों के अंतर पर निर्भर रही है, लेकिन बैंक ऑफ जापान द्वारा हाल ही में की गई दर वृद्धि और भविष्य में इसके और बढ़ने की उम्मीद के साथ-साथ यूएस फेड की संभावित नरमी ने इस अंतर को काफी कम कर दिया है। इससे कैरी ट्रेड कम आकर्षक हो गया है। जापानी मंत्रालय ने विदेशी मुद्रा बाजार में जापानी येन में मजबूती लाने के लिए 26 अप्रैल, 2024 से 29 मई, 2024 के बीच रिकॉर्ड 9.8 ट्रिलियन जापानी येन (62.2 बिलियन यूएस डॉलर) खर्च किए। यह हस्तक्षेप अप्रैल 2024 में यूएसडी/जेपीवाई विनिमय दर के 160.21 के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद आया, जिससे बैंक ऑफ जापान को हस्तक्षेप करना पड़ा और 3 मई को एक यूएस डॉलर के मुकाबले जापानी येन की कीमत घटकर 151.92 आ गई।

जनवरी 2025 में बैंक ऑफ जापान ने 0.5% तक ब्याज दरें बढ़ा दीं, जिससे यूएस फेड की उच्च दरों के साथ अंतर कम हो गया। इससे डॉलर पर दबाव कम हुआ, जबकि जापानी येन को मजबूती मिली। बैंक ऑफ जापान की जुलाई 2025 की बैठक में 0.5% की दर पर स्थिर कर दिया गया है, तथापि केंद्रीय बैंक ने आर्थिक आंकड़ों के आधार पर भविष्य में मुद्रास्फीति और वेतन वृद्धि की संभावना के संकेत दिए हैं। बैंक ऑफ जापान ने अपने विनिमय व्यापार कोष (ईटीएफ) और जापान रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स को बेचने की घोषणा की है। अभी यूएस डॉलर और जापानी येन की कीमत एक छोटे दायरे में फंसी हुई है और फिलहाल यह कीमत ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं जा रही। इसके लिए जापान के केंद्रीय बैंक की अगली बैठक में मिलने वाले संकेतों का इंतजार किया जा रहा है। यदि बैंक ऑफ जापान सख्त रुख अपनाता है या बैंक ऑफ अमेरिका नरम रुख अपनाता है, तो डॉलर/येन की कीमत लगभग 145 तक गिर सकती है। लेकिन अगर बैंक ऑफ जापान नरम रुख अपनाता है और बैंक ऑफ अमेरिका सख्त रुख अपनाता है, तो डॉलर/येन की कीमत बढ़कर लगभग 149.358 तक जा सकती है।

यथा 24 सितंबर, 2025 को एक यूएस डॉलर के मुकाबले जापानी येन 147.6130 पर बंद हुआ।

ब्राज़ीलियाई रियाल

NIS

ब्राज़ीलियाई रियाल (बीआरएल) में उतार-चढ़ाव देखा गया है। इसकी वजह है कि लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा ने मौजूदा राष्ट्रपति जाइर बोलसोनारो को कड़े मुकाबले में हराकर ब्राज़ील के अगले राष्ट्रपति पद के लिए जीत हासिल कर ली है।

सेलिक रेट कही जाने वाली ब्राज़ील की बेंचमार्क ब्याज दर फिलहाल 15% प्रति वर्ष है। यह दर ब्राज़ील के केंद्रीय बैंक (बांको सेंट्राल दो ब्राज़ील) ने सितंबर 2025 की हालिया बैठक में तय की थी। यह लगातार दूसरी बैठक है, जिसमें इस दर को इसी स्तर पर बनाए रखा गया है। आर्थिक विकास की धीमी गति के बावजूद केंद्रीय बैंक ने यह निर्णय मुद्रास्फीति के संभावित खतरे और जारी आर्थिक अनिश्चितता के चलते लिया है।

यथा 23 सितंबर, 2025 को ब्राज़ीलियाई रियाल और यूएस डॉलर की दर 8 दिवसीय 21 दिवसीय अपनी ईएमए के आसपास है। यह 50 दिवसीय ईएमए से 1.29% और 100 दिवसीय ईएमए से 2.4% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। 8 दिवसीय ईएमए ऊपर की ओर जा रही है, जो बुलिश का संकेत देती है। एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन से ऊपर है, जो सकारात्मक रुझान और अपट्रेंड की पुष्टि करती है।

यथा 24 सितंबर, 2025 को एक यूएस डॉलर के मुकाबले बीआरएल 5.3314 पर बंद हुआ।

मेक्सिकन पेसो

US\$

पेसो की मजबूती का कारण इसकी स्थिरता और मेक्सिको की रिकॉर्ड उच्च ब्याज दरें हैं। यही वजह है कि एक मुद्रा में उधार लेकर पेसो में निवेश करना एक आकर्षक विकल्प बन गया है। यथा 7 अगस्त, 2025 को बैंक ऑफ मेक्सिको (बैंक्सिको) की बेंचमार्क ब्याज दर 7.75% रही। वार्षिक मुद्रास्फीति में आई गिरावट के चलते उस समय यह दर 25 बेसिस पॉइंट घटाकर तय की गई थी। यह कटौती 2024 में शुरू हुई दरों में कमी की प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें 2024 की शुरुआत के 11.25% की उच्च दरों में धीरे-धीरे गिरावट आई है।

मेक्सिकन पेसो कमजोर होकर 18.35 प्रति यूएस डॉलर के करीब पहुंच गया, जो जुलाई 2024 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर था। यह गिरावट तब आई जब फेडरल रिजर्व द्वारा दर निर्धारण के बाद यूएस डॉलर ने फिर से मजबूती हासिल की और निकट भविष्य में दरों में कटौती की संभावनाएं कम हो गईं और 'कैरी ट्रेड' का लाभ कम हो गया। मेक्सिको में, अगस्त में हेडलाइन मुद्रास्फीति लगभग 3.57% और कोर मुद्रास्फीति लगभग 4.23% रही, जो कि नियंत्रित है। फिर भी बैंक्सिको को आक्रामक दर कटौती के प्रति सतर्क करती है। इस बीच, वृद्धि के आकलन कुछ कमजोर हुए हैं, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई है और निजी खर्च की संभावना भी कम हुई है, जिससे पेसो-आधारित आस्तियों की मांग में गिरावट आई है। यूएस यील्ड में वृद्धि और एमएक्सएन की तीव्र वृद्धि के बाद सुधार जैसे बाहरी दबाव भी इस गिरावट का कारण बने।

यथा 24 सितंबर, 2025 को एक यूएस डॉलर के मुकाबले एमएक्सएन 18.40 पर बंद हुआ।

न्यू ताइवान डॉलर

NZ\$

न्यू ताइवान डॉलर 1949 से ताइवान की आधिकारिक मुद्रा है। ताइवान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्यात, विशेष रूप से सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों के निर्यात पर निर्भर है। एआई और नई तकनीकों की अच्छी मांग के चलते 2025 की पहली छमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अच्छा रहा। सरकारी पूर्वानुमान के अनुसार, 2025 में ताइवान की जीडीपी में वृद्धि होगी और यह 4.45% तक पहुंच जाएगी, लेकिन 2026 में यूएस टैरिफ के कारण इस वृद्धि की गति धीमी हो जाने की आशंका है।

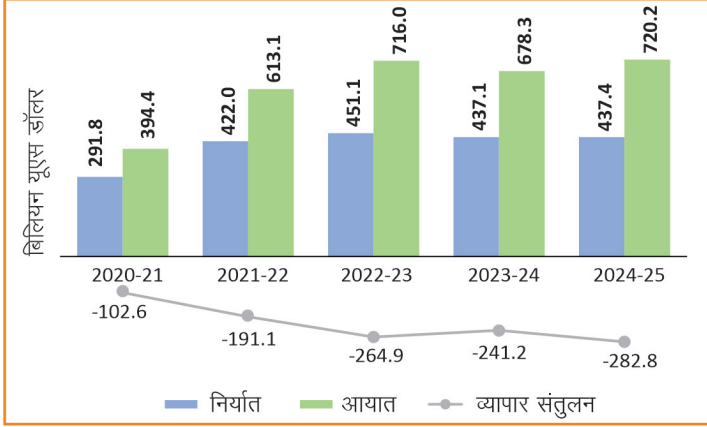
वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार की चिंताओं को देखते हुए, ताइवान के केंद्रीय बैंक ने मार्च 2024 से अपनी बेंचमार्क डिस्काउंट दर 2% पर बनाए रखी है। मुद्रास्फीति चिंता का विषय है, लेकिन केंद्रीय बैंक को इसके नियंत्रित रहने और 2025 के लिए ग्राहक मूल्य सूचकांक के 1.76% पर रहने की उम्मीद है। ताइवान की मुद्रा, न्यू ताइवान डॉलर हाल ही में उल्लेखनीय रूप से मजबूत हुई और यूएस डॉलर के मुकाबले पिछले दो वर्षों का सर्वोच्च स्तर छूते हुए इस मई की शुरुआत में लगभग 29.795 ताइवानी डॉलर तक पहुंच गई थी। इसके बाद, यह लगभग एक यूएस डॉलर के मुकाबले 30.15 ताइवानी डॉलर पर स्थिर हुई। इस ऊंचाई का श्रेय आंशिक रूप से ताइवान के केंद्रीय बैंक की उस रणनीति को जाता है, जिसमें उन्होंने बाजार की वृद्धि की उम्मीदों को खुला छोड़कर सट्टेबाजी को कम करने का प्रयास किया था। अगले 12 महीनों में, लगभग एक यूएस डॉलर के मुकाबले ताइवानी डॉलर के 30.44 पर ट्रेड करने का अनुमान है।

यथा 24 सितंबर, 2025 को एक यूएस डॉलर के मुकाबले ताइवानी डॉलर 30.353 पर बंद हुआ। ■

भारत की आर्थिक वृद्धि

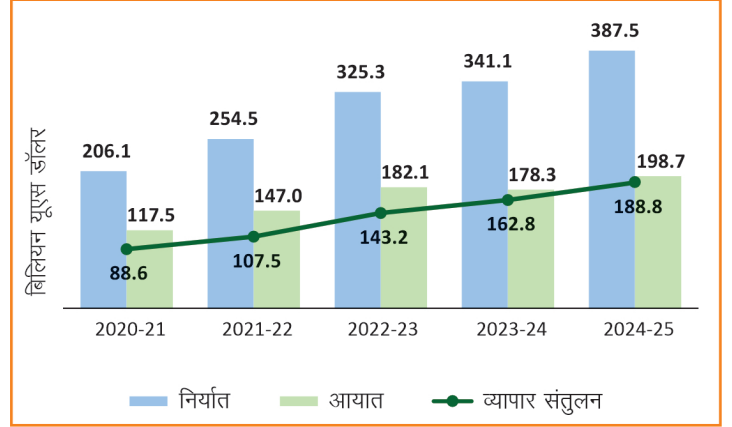
सौजन्य: शोध एवं विश्लेषण समूह

भारत का मर्चेंडाइज़ व्यापार



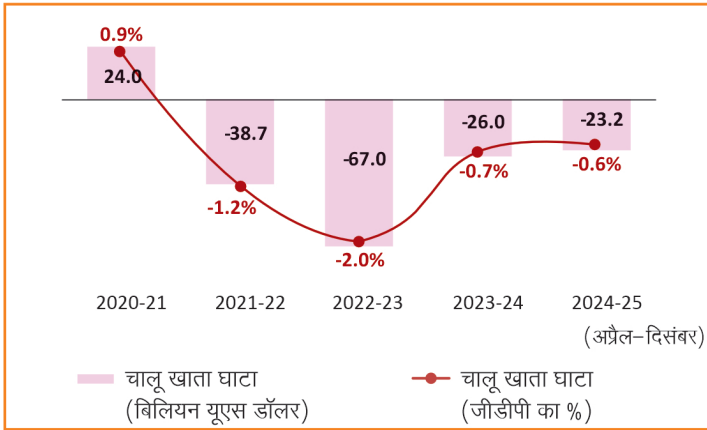
स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

भारत का सेवा व्यापार



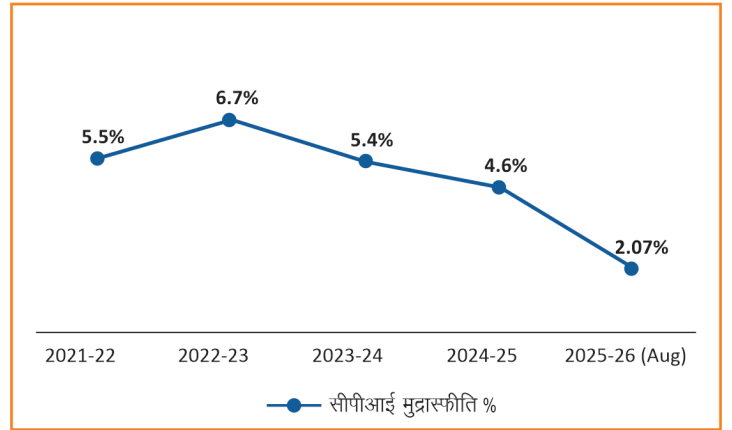
स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

चालू खाता घाटा



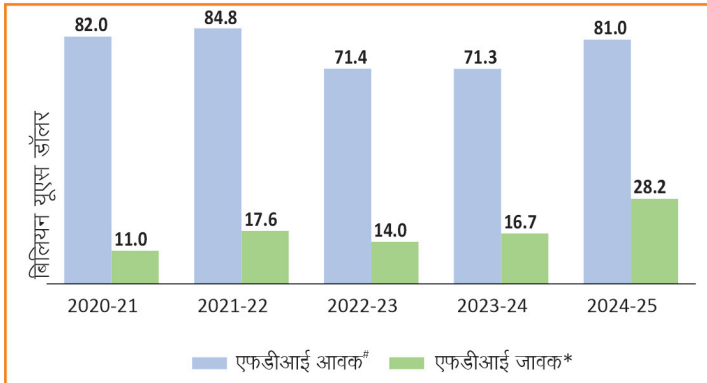
स्रोत: आरबीआई

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)



स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह

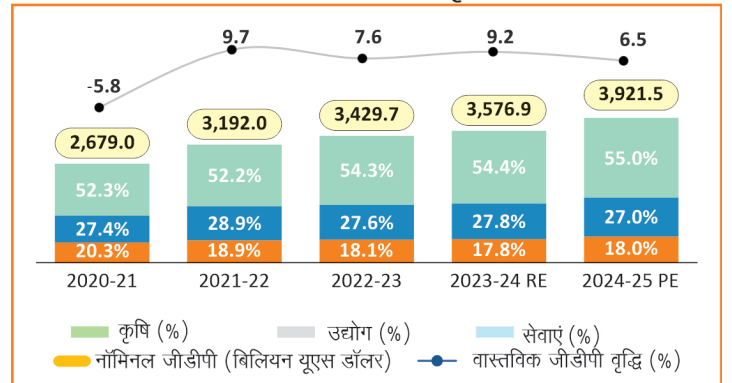


नोट: * एफडीआई जावक वास्तविक आंकड़े दर्शाते हैं और इसमें इक्विटी, ऋण, इन्वोक की गारंटियां शामिल हैं।

* एफडीआई आवक में इक्विटी, पुनर्निवेश आय और अन्य पूंजी शामिल है।

स्रोत: आरबीआई और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

भारत की आर्थिक वृद्धि



नोट: क्षेत्रवार प्रतिशत के आंकड़े जीडीपी में क्षेत्रवार हिस्सेदारी को दर्शाते हैं। आरई- संशोधित अनुमान; पीई- अंतिम अनुमान

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान (आईआईएफ) एवं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार